दी नेक्स्ट पोस्ट

साप्ताहिक

7 | 3 यूपी में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर खड़े ट्रेलर के पीछे घुसी बलेनो कार | 5 हिन्दू युवती को षडयंत्र के तहत भगाकर ले गया आशिक अंसारी, गांव में तनाव का माहौल | 8 दनादन क्रिकेट का नया रोमांच...

UPHIN51019 | वर्ष: 02, अंक: 17 | पृष्ठ संख्या: 8 | मूल्य: 1.00 रू. | सोमवार 21 अक्टूबर, 2024

शरीर पर मिले 20 से ज्यादा गहरे घाव नाक और पैर-हाथ काटे

झोपड़ी में किसान घनश्याम सैनी का खून से लथपथ शव जिस जगह मिला, वहां से खेत तक जगह–जगह खून के छींटे मिले। इसके अलावा आसपास की गोभी की फसल भी क्षतिग्रस्त मिली। झोपड़ी में पड़ी चारपाई का बिस्तर भी अलग सिमटा पड़ा था। इससे साफ हो रहा है कि घनश्याम ने जान बचाने के लिए हत्यारोपियों से जमकर संघर्ष किया।

'मेरे सामने हुई प्रेमी की हत्या...' आकाश हत्याकांड में सामने आई प्रेमिका

बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र में युवक आकाश की हत्या कैसे की गई, इसका पता पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं चला है। फिलहाल, चिकित्सकों ने मौत की वजह जानने के लिए बिसरा सुरक्षित कर लिया है। उधर, पुलिस को जो तहरीर दी गई है उसमें युवक की प्रेमिका को गवाह बनाया गया है। प्रेमिका का कहना है कि युवक की हत्या उसके सामने की गई थी।

2 Km तक फैलेगी दीपों की आभा, इस बार कर सकेंगे ऑनलाइन दीपदान

दीपोत्सव के लिए अयोध्या को सजाने का काम तेज कर दिया गया है। अयोध्याधाम में दो किलोमीटर तक दीपोत्सव की आभा बिखरती नजर आएगी। रामपथ से लेकर धर्मपथ तक भव्य लाइटिंग की जा रही है। रामायण युग का अहसास कराते गेट भी बनाए जा रहे हैं। राम की पैड़ी पर लक्ष्मण व सीता द्वार का निर्माण अंतिम चरण में है। 25 अक्तूबर तक अयोध्याधाम को सजाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

एनकाउंटर पर सियासत

अखिलेश बोले– सरकार का नया तरीका, राजभर ने किया पलटवार, तो क्या पुलिस माला पहनाएगी

बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद सियासी माहौल भी गरमा गया है। यूपी पुलिस ने गुरुवार दोपहर रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों में शामिल सरफराज और तालिब का एनकाउंटर किया है। वहीं इसके बाद सपा और कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। मुठभेड़ के बाद बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से 2 पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। सरफराज और मोहम्मद तालिब को गोली लगी है। यूपी पुलिस के अनुसार आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। हिंसा के बाद से बहराइच में स्थिति सामान्य बनी हुई है।

सरकार के काम करने का नया तरीका: अखिलेश यादव

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं सरकार की नाकामी के कारण हो रही हैं। एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, और भी कई परिभाषाएं हैं जो सरकार ने बनाई है। अखिलेश ने कहा कि अगर एनकाउंटर से ही कानून–व्यवस्था बेहतर हो रही होती तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में दूसरे प्रदेशों से अच्छा होता, यह प्रशासनिक विफलता थी कि जब वहां (बहराइच) कार्यक्रम पुलिस की जानकारी में था तो आखिरकार वे शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न क्यों नहीं करवा पाए? एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, यह इस सरकार के काम करने का नया तरीका है... यह कहां की न्याय व्यवस्था है?

एनकाउंटर रोज हो रहे हैं: अविनाश पांडे

कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने बहराइच एनकाउंटर पर कहा कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार के एनकाउंटर रोज हो रहे हैं। क्या उस एनकाउंटर के पीछे कोई ठोस सबूत है? बहराइच जल रहा है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और वहां पर शांति स्थापित करें। बहराइच एनकाउंटर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "सरकार शुरू से ही फर्जी एनकाउंटर करा रही है। वे सिर्फ अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब पुलिस किसी को पकड़ने जाएगी और उनके ऊपर कोई गोलियों की बौछार करेगा, तो क्या पुलिस उसे माला पहनाएगी या उस पर फूलों की वर्षा करेगी? जिंदा या मुर्दा, उन्हें (अपराधियों को) पकड़ना है। अपराध अगर किया है तो जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या जेल में, देश–प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए।"

प्रशासन घटना के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार: सपा

वहीं, समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बहराइच में जो हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, उसमें पुलिस, प्रशासन और सरकार की पूरी विफलता थी। कई घंटों तक बहराइच में आगजनी होती रही। वहां पुलिस नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा और वहां दंगा भड़क गया। इसमें पूर्ण रूप से वहां का पुलिस–प्रशासन दोषी है, जिसे मालूम था कि नवरात्र के बाद लोग वहां जाएंगे। प्रदेश सरकार और वहां का प्रशासन इस घटना के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं।

मूत विसर्जन के दिन विवाद के बाद हत्या

गौरतलब है कि बहराइच के हरदी इलाके के महाराजगंज कस्बे में रविवार 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के लिए यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान दो समुदायों के बीच विवाद पनप गया। तनावपूर्ण माहौल में हिंदू पक्ष के रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप दूसरे पक्ष पर लगा। इस सिलसिले में महराजगंज निवासी अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ सरफाराज, फहीम, राजा उर्फ साहिर खान, रेहुआ मंसूर के ननकऊ व मारूफ अली समेत 10 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद बहराइच में दो दिनों तक हिंसा व्याप्त रही। भीड़ ने घरों, दुकानों, शोरूम, अस्पतालों, वाहनों आदि में आग लगा दी, जिसके बाद बहराइच पुलिस ने कई अज्ञात और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज कीं। हिंसक प्रदर्शन के आरोप में पुलिस 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।

बहराइच लहसा के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद सियासत तेज कांग्रेस नेता अजय राय ने उठाए सवाल तो राजभर ने दिया जवाब

बहराइच एनकाउंटर के बाद सियासी माहौल गरमा गया है। यूपी पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों में शामिल सरफराज और तालिब का एनकाउंटर किया। सपा और कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनमें से 2 घायल हैं। विपक्ष ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं जबकि योगी सरकार के मंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है।

बच्चों का आपत्तिजनक वीडियो बेच रहा था किशोर, पर्दाफाश के बाद मचा हड़कंप

तमिलनाडु पुलिस की जांच में सामने आया गोरखपुर के कई छात्रों का नाम
साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक को भेजा बाल संप्रेक्षण गृह,दूसरे की तलाश
गोरखनाथ क्षेत्र का राज तिवारी ने रुपये का लालच देकर कई छात्रों को फंसाया

संवाददाता, गोरखपुर। जिले के स्कूलों में पढ़ने वाले कई किशोर के इंस्ट्राग्राम अकाउंट से देश भर में अश्लील वीडियो बेचने का मामला सामने आया है।

तमिलनाडु पुलिस के हाथ वीडियो लगा तो इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को हुई। अधिकारियों के निर्देश पर सक्रिय हुई साइबर थाना पुलिस ने कूड़ाघाट क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के छात्र को अभिरक्षा में लेकर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जहां से बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। गोरखनाथ क्षेत्र में रहने वाले एक अन्य छात्र की तलाश कर रही है। पूछताछ में छात्र ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने नेकोग्राम एप पर अकाउंट बनाए है।

> **छात्र का मोबाइल कब्जे में ले लिया गया है। जांच में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। पूछताछ में जिन लोगों का नाम सामने आया है उनकी तलाश चल रही है।सरगना के पकड़े जाने पर गिरोह का पर्दाफाश होगा।**
>
> –सुधीर कुमार जायसवाल
> एसपी क्राइम

इसके अलावा वह टेलीग्राम के जरिए भी डार्क वेब सेलर का काम करता था, जिसकी मदद से वह करीब 4000 वीडियो को बेचने में अब तक सफल रहा।

साइबर पुलिस को उसकी इस साइट पर कई अश्लील चैटिंग भी मिली है। जांच में सामने आया कि राज तिवारी बच्चों का आपत्तिजनक वीडियो संचालन करने वाले गिरोह का सरगना है। कूड़ाघाट के अलावा उसने जिले के कई स्कूलों के छात्रों को अपनी जाल में फंसाया है और उनके टेलीग्राम व इंस्टाग्राम एकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है। गोरखनाथ क्षेत्र में रहने वाले एक अन्य छात्र की भी साइबर थाना पुलिस को तलाश हैं जिसने जिसने 100 से अधिक बच्चों के अश्लील वीडियो देश भर में बेचे हैं।

सम्पादकीय

विश्व का सबसे सम्मानित कहा जाने वाला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन शोधकर्ताओं डारोन एसिमोग्लू, साइमन जानसन और जेम्स ए. राबिन्सन को दिया गया है

अमीर–गरीब देशों के फर्क का राज़

विश्व का सबसे सम्मानित कहा जाने वाला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन शोधकर्ताओं डारोन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए. रॉबिन्सन को दिया गया है। उन्होंने इस बात का पता किया है कि आखिर वे कौन से तथ्य हैं जिनके चलते विभिन्न देशों के बीच अमीरी–गरीबी का फर्क पैदा होता है। उन्होंने इसे दूर करने के कुछ उपाय बताये हैं जिन पर अमल कर वैश्विक गैरबराबरी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। देखना यह होगा कि जिन देशों के पास दुनियावी बदलाव करने की ताकत है, वे इस पर कितना अमल करते हैं। जाहिर है कि ऐसा कर वे स्वयं अपने रुतबे तथा दबदबे को खत्म करेंगे। इस रिसर्च को तो उन राष्ट्राध्यक्षों को ध्यान से पढ़ने, समझने और उसे क्रियान्वित करने की ज़रूरत है जो अपने देश के नागरिकों को खुशहाल बनाना चाहते हैं। यहां सवाल विश्व के सम्पन्न देशों की सूची में आना मात्र नहीं है वरन अपने नागरिकों के रहन–सहन के स्तर को ऊंचा करना और उन्हें एक गरिमामय जीवन प्रदान करना भी है। एसिमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन ने अपने सामूहिक अध्ययन एवं विशद विश्लेषण से स्पष्ट किया है कि कुछ देश क्यों अमीर हो गये और अनेक किसलिये गरीब हैं। इसके लिये उन्होंने कुछ इलाकों के उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं जिनके कुछ क्षेत्र एक देश में हैं तो कुछ दूसरे देश में। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने सोमवार को इन अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देने का ऐलान करते हुए उनके काम की महत्ता को रेखांकित किया। 5 क्षेत्रों में दिये जाने वाला नोबेल आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले को 'स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार' कहलाता है। समिति ने कहा कि पुरस्कार के लिये चयनित अर्थशास्त्रियों ने पहली बार सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रतिपादित करते हुए देशों की समृद्धि में उनके योगदान की वैज्ञानिक तरीके से मीमांसा की है। अपने शोध से उन्होंने यह भी बतलाया कि कैसे लोकतंत्र एवं समावेशी सामाजिक संस्थानों के जरिये राष्ट्र का विकास सम्भव है। एसिमोग्लू, जॉनसन तथा रॉबिन्सन के इस शोध ने बताया है कि खराब कानून व्यवस्था तथा नागरिकों का शोषण करने वाली संस्थाएं या देश सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकते। पुरस्कार समिति का यह कहना कि, 'देशों के बीच आय के अंतर को खत्म करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है', ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था के दुष्प्रभावों की ओर छिपा संकेत है जिसके माध्यम से कई देशों की राजनैतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को बर्बाद कर उन्हें पिछड़ा बना दिया गया है। उपरोक्त अर्थशास्त्रियों ने यूरोपीय उपनिवेशों द्वारा प्रवर्तित विभिन्न राजनीतिक व आर्थिक प्रणालियों का विशेलेषण कर संस्थाओं एवं सम्पन्नता के अंतर्संबंधों का पता किया है। उन्होंने इसके उपाय भी बताये हैं कि कैसे इन संस्थाओं को सक्षम कर विकास में उनका सहयोग लिया जा सकता है। इसके कारण यह शोध विश्व भर के उन देशों के लिये मददगार हो सकता हैं जो गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं। उनकी शोध बतलाती है कि कैसे दुनिया के सर्वाधिक सम्पन्न 20 प्रतिशत देश अब विश्व के सबसे गरीब 20 फीसदी देशों से 30 गुना अमीर हैं। कई विपन्न देश समृद्ध तो हुए हैं लेकिन वे अमीर देशों की तुलना में अब भी कई गुना कम सम्पन्न हो सके हैं। इसका कारण उन्होंने भौगोलिक या सांस्कृतिक फ़र्क नहीं, सामाजिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में अंतर को जिम्मेदार बतलाया है। अपनी बात को विस्तार देते हुए तीनों ने बताया है कि उनके मॉडल के तीन हिस्से हैं। पहला तो यह देखना होगा कि संसाधनों का आवंटन कैसे हुआ है; तथा निर्णय लेने की शक्ति किस समूह के पास है। दूसरा यह कि कभी–कभार जनता को सत्तारुढ़ अभिजात वर्ग को संगठित कर सत्ता का इस्तेमाल करने का जब अवसर मिलता है तो समाज में निर्णय लेने की शक्ति कहीं अधिक हो जाती है। तीसरी है प्रतिबद्धता। सत्तारुढ़ अभिजात वर्ग के लिये एकमात्र विकल्प जनता को निर्णय लेने की शक्ति सौंपना है। उपरोक्त निष्कर्षों को यदि गौर से देखा जाये तो बात अंततः स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रणाली एवं ईमानदार संवैधानिक संस्थाओं की आवश्यकता पर जाकर ठहरेगी। किसी भी देश में चाहे जिस विचारधारा की सरकार हो उसके सही या गलत होने का पैमाना यही होगा कि वह इन संस्थाओं को कितनी स्वंतत्रतापूर्वक काम करने देती है। सरकारों का केवल लोकतांत्रिक प्रणाली के जरिये चुना जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से शासन करना भी उतना ही ज़रूरी है। साथ ही आवश्यक है लोकतांत्रिक संस्थाओं को सम्प्रभुता प्रदान करना। भारत समेत अनेक देशों के ही उदाहरण देखें तो शासकों की प्रवृत्ति शक्तियों के केन्द्रीकरण में है। हमारे ही देश में संस्थाएं कमजोर होती गयी हैं और राज्य शक्तिशाली। बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों की समझ को इस प्रकार से भोंथरा कर दिया गया है कि शक्तिशाली सरकारों वाले देश ही सम्पन्न हो सकते हैं। नोबेल पुरस्कृत उपरोक्त अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन का दायरा देशों की आर्थिक व्यवस्था तक ही सीमित रखा है, लेकिन इसे समझने के लिये अपनी सोच को विस्तार दिया जाये तो यह भी साफ होता जायेगा कि संस्थाओं की जिस मजबूती की बात की गयी है, उसके अभाव में किसी भी देश में न केवल आर्थिक अव्यवस्था हो जायेगी वरन सामाजिक एवं राजनीतिक अराजकता फैलने में भी देर नहीं लगेगी। यह आशंका तीसरी दुनिया कहे जाने वाले एशियाई, अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी उन देशों को लेकर अधिक है जो अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। भारत के पड़ोसी देशों– श्रीलंका एवं बांग्लादेश में ऐसा होता हुआ दिख चुका हैं। भारत को इस शोध पर गम्भीर मनन करना चाहिये।

हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस को महाराष्ट्र में अधिक सावधान रहना होगा

अपनी अनुकूलता और समझौते की वजह से 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य भाजपा से आमने–सामने की लड़ाई करना था और भाजपा विरोधी वोटों को विभाजित नहीं करना था। गठबंधन ने चिड़चिड़े मुद्दों को पीछे छोड़ दिया और इसके कारण चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहा। कांग्रेस पार्टी को अपने इंडिया गठबंधन सहयोगियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव को ठीक से नहीं लड़ा, जिससे भाजपा को दस साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद तीसरी बार जीत हासिल करने का मौका मिल गया। अधिकांश एग्जिट पोल ने कांग्रेस की स्पष्ट जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भाजपा ने 90 में से 48 सीटें हासिल कीं, एक ऐसी जीत जिसने खुद भाजपा को भी चौंका दिया।

यदि कांग्रेस हरियाणा में जीत जाती तो कांग्रेस के पुनरुत्थान की कहानी को बढ़ावा मिलता। हालांकि, कांग्रेस ने हाल ही में आंतरिक संघर्षों के कारण यह पांचवां विधानसभा चुनाव गंवा दिया। इसके पहले वह पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार चुकी थी। अब यह अनिश्चित है कि इंडिया गठबंधन में उसकी साझेदार राजनीतिक पार्टियां भाजपा के खिलाफ लड़ाई में उसके साथ एकजुट होंगे या नहीं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के लिए आप के साथ गठबंधन जीत के लिए फायदेमंद होता है या नहीं, इस पर बहस हो रही है। दूसरे, हार का असर महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले आगामी चुनावों पर पड़ेगा। हरियाणा के नतीजों का तत्काल असर दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे पर पड़ने की संभावना है। तीसरे, यह अनिश्चित है कि कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन होगा या नहीं। आप पहले ही कह चुकी है कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी।

अपनी अनुकूलता और समझौते की वजह से 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य भाजपा से आमने–सामने की लड़ाई करना था और भाजपा विरोधी वोटों को विभाजित नहीं करना था।

गठबंधन ने चिड़चिड़े मुद्दों को पीछे छोड़ दिया और इसके कारण चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहा। उन्होंने भाजपा को हराने के एकमात्र उद्देश्य से काम किया और कुछ हद तक इसमें सफल भी रहे। भाजपा का बहुमत कम हो गया और जेडी(यू) और टीडीपी की मदद से सरकार बनानी पड़ी। हरियाणा की हार ने गठबंधन के भीतर की स्थिति को बदल दिया है, जिसके बाद इंडिया ब्लॉक की अन्य राजनीतिक पार्टियों को कांग्रेस पर बढ़त मिल गयी है। साझेदार शायद थोड़ी अधिक संयमित और समझ–बूझ से निर्णय करते हुए अब कांग्रेस के साथ काम करेंगे। अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने यह नहीं कहा है कि इंडिया ब्लॉक खत्म हो गया है। इसके विपरीत, हार के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बयान से संकेत मिलता है कि कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश ने कहा, 'मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया ब्लॉक बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस–सपा का गठबंधन बरकरार रहेगा।'

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि उसने तीन महीने पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। कांग्रेस तथा आप को कोई सीट नहीं मिली थी। अन्य सहयोगियों ने कांग्रेस की अति आत्मविश्वास और सीट बंटवारे के प्रति उसके कठोर रवैये की आलोचना की।

लोकसभा चुनाव में अपनी संख्या दोगुनी करने वाली कांग्रेस हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कमजोर पड़ गयी है। अधिकांश एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस की आश्चर्यजनक जीत का संकेत दिया क्योंकि भाजपा को 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा और असंतुष्ट लोगों के एक वर्ग से निपटना पड़ा। हालांकि, भाजपा ने सबको चौंका दिया और हरियाणा में अपनी सबसे प्रभावशाली जीत दर्ज की। इस ग्रामीण राज्य में किसी भी पार्टी को कभी भी तीसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल नहीं हुई थी।

महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस को सीट बंटवारे के फॉर्मूले और चुनाव से पहले ही ठाकरे को सीएम के चेहरे के रूप में पेश करने की शिवसेना की मांग पर अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है।

आप ने हरियाणा चुनाव में कोई सीट नहीं जीती, लेकिन उसे लगभग 1.78 प्रतिशत वोट मिले। अगर कांग्रेस ने आप के साथ गठबंधन किया होता तो निस्संदेह यह इंडिया ब्लॉक की झोली में जुड़ जाता। शिवसेना नेता संजय राऊत के अनुसार, कांग्रेस ने छोटी पार्टियों और उनके सहयोग के प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया। तृणमूल कांग्रेस, आप, शिवसेना (उद्धव), नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरजेडी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य पर्टियों के नेताओं ने हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी के लिए कांग्रेस की आलोचना की। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बुधवार को संपादकीय में कहा गया, 'किसी ने नहीं सोचा था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार फिर बनेगी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अति आत्मविश्वास और स्थानीय कांग्रेस नेताओं के अहंकार के कारण पार्टी की हार हुई।'

आपदा या कमाई का अवसर

सरकार ने फिर से कबाड़ घोषित वाहनों, अर्थात दस साल पुराने डीजल वाहन और पंद्रह साल पुराने पेट्रोल वाहनों की धर–पकड़ तेज करने का फिसला किया है

सरकार ने फिर से कबाड़ घोषित वाहनों, अर्थात दस साल पुराने डीजल वाहन और पंद्रह साल पुराने पेट्रोल वाहनों की धर–पकड़ तेज करने का फिसला किया है। दिल्ली में 60 लाख ऐसे वाहन है और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर उनकी पार्किंग भी गैरकानूनी है, उनको चलाना तो अपराध है ही। और दिल्ली सरकार की मुखिया आतिशी सिंह को यहां के लेफ्टि. गवर्नर वी.के. सक्सेना के आदेश को आगे बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं हुई। अगर दिल्ली की तीनों सरकारें अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लाट साहब वाली तीसरी सरकार किसी सवाल पर एक ही दिशा में काम करने पर जुटे तो इसे ट्रिपल इंजन सरकार कहा जाए या नहीं, इस बात पर विवाद हो सकता है लेकिन अगर वे तीनों किसी बड़ी समस्या को निपटाने के सवाल पर सक्रिय हो तो सामान्य ढंग से खुश होना बनाता है।

दिल्ली में प्रदूषण वाले मौसम की शुरुआत से पहले उसकी रोकथाम के नाम पर ऐसा ही हो रहा है। ऐसा हर साल होता है और स्वास्थ्य के नुकसान के साथ ही काफी सारे धन की बर्बादी को जान समझ लेने के बाद भी कहा जा सकता है कि कुछ मामलों में हल्का फर्क आया है। पराली अर्थात धान की खेत में छोड़ी डंडियों या पुआल को वहीं जला देने से फैलने वाले धुएं की मात्रा और सघनता में कमी आई है और कई कदम भी उठाने का प्रयास हुआ है। ऐसा सारे कदमों के लिए नहीं कह सकते पर बेतहाशा बढ़ती गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को भी नुकसानदेह गिनना ऐसा ही कदम है जो कैंसर से लेकर न जाने कितनी बीमारियों का कारण माना जाता है।

इसके साथ ही यह भी हुआ है कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले भी आ गए हैं। मुश्किल यह है कि ऐसा सिर्फ कमाई के काम में लगे चंद लोग नहीं हैं, खुद सरकार उनकी सेवा में लगी दिखती है। और वह गलती करने वालों को पकड़ने या सजा देने की जगह अपने नागरिकों को सजा देने, वसूली करने और उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ की छूट दे रही है। जो लोग प्रदूषण रोकने के मानकों पर खरा उतरने वाले वाहन नहीं बना रहे हैं सरकार उनके वाहनों की बिक्री बढ़वाने का जिम्मा लेकर काम करती लग रही है और यह करते हुए उसका खजाना भी भर रहा है। जिन नागरिकों की जेब कट रही है या जिनको प्रदूषण की मार झेलनी होती है उनको ही दोबारा वहां खरीदने का बोझ उठाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को नाश होने दिया है। अकेले दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की संख्या में 2021–22 में सीधे 35.4 फीसदी कमी हो गई है। 2020–21 में दिल्ली में 1.2 करोड़ पंजीकृत वाहन थे जो 2021–22 में 79.2 लाख रह गए। दिल्ली सरकार ने 48,77,646 वाहनों का पंजीयन समाप्त किया था और बड़े पैमाने पर पुराने वाहनों की धर–पकड़ से यह 'सफलता' मिली थी पर ये सारे वाहन किसी न किसी के उपयोग में थे, जीवन चला रहे थे, उनकी शान थे। यह और बात है कि हमको–आपको चूं की आवाज भी सुनाई नहीं दी।

अब फिर सरकार ने फिर से कबाड़ घोषित वाहनों, अर्थात दस साल पुराने डीजल वाहन और पंद्रह साल पुराने पेट्रोल वाहनों की धर–पकड़ तेज करने का फिसला किया है। दिल्ली में 60 लाख ऐसे वाहन है और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर उनकी पार्किंग भी गैरकानूनी है, उनको चलाना तो अपराध है ही। और दिल्ली सरकार की मुखिया आतिशी सिंह को यहां के लेफ्टि. गवर्नर वी.के. सक्सेना के आदेश को आगे बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं हुई। सक्सेना साहब इस काम को मिशन भाव से कर रहे हैं। कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नामक संस्था भी सर्दियों के पहले बढ़ते प्रदूषण के नाम पर अपनी रिपोर्ट और सुझाव के साथ हाजिर है। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उनका बैर प्रदूषण से है या पुरानी गाड़ियों से या फिर सबका उद्देश्य नई गाड़ियां बिकवाना है। न तो प्रदूषण चेक करके देखने की जरूरत मानी गई ना ऐसे वाहनों को देहात या कम प्रदूषण वाले इलाकों में भेजने का या सस्ते निर्यात का विकल्प सोचा गया। सीधे दामिल फांसी। जिन गाड़ियों का पंजीकरण निरस्त हुआ है उनमें बहुत ऐसी भी है जिनको ज्यादा अवधि का लाइसेंस इन्हीं सरकारों ने दिया और जिनसे ज्यादा अवधि का रोड टैक्स वसूला जा चुका है। सुनते हैं कि इस आदेश के खिलाफ कुछ लोग अदालत गए थे पर उनके मुकदमे का क्या हुआ? यह खबर कहीं से नहीं आई है।

दूसरी ओर, हर कहीं पुराने वाहनों की धर–पकड़ हो रही है। सिपाहियों को सिर्फ निर्देश नहीं है, संभवतः कुछ बोनस भी दिया जा रहा है। कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है कि दिल्ली में 5928675 ऐसी गाड़ियां हैं लेकिन सिर्फ कुछ हजार गाड़ियां ही पकड़ी गई हैं। लाट साहब सक्सेना जी अलग लगे पड़े हैं। सो देखते जाइए कि इस बार के धुंध और प्रदूषण के मौसम में कितनी गाड़ियां कुर्बान होती हैं। जाहिर तौर पर इन सबके पीछे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2020–21 के बजट में निजी वाहनों और व्यावसायिक वाहनों को जोड़कर करीब अस्सी लाख गाडियों को 'स्क्रैप' करने की बात कही है। तब भी कहीं से कोई आवाज नहीं आई थी। इसके बाद नई नीति के कुछ संकेत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिए थे। यह फैसला सिर्फ नई गाडियों के लिए नहीं था बल्कि उन गाडियों पर भी लागू हुआ जिनका पन्द्रह और बीस साल का रोड टैक्स पहले वसूला जा चुका था। कहना न होगा कि मामला दिल्ली भर का नहीं है। अगर अकेले दिल्ली में एक साल मे 48 लाख से ज्यादा गाड़ियां कबाड़ बन गईं और अब 60 लाख गाड़ियों का पंजीकरण खत्म हुआ है तो देश भर की संख्या से निर्मला जी और गडकरी साहब बहुत खुश होंगे ही।

माना जाता है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा कर रही थीं तब उन्होंने जानबूझ कर गलत आंकड़ा दिया। उन्होंने जो संख्या बताई वह असल संख्या के लगभग चालीस फीसदी भी नहीं मानी जाती।

जानकार मानते हैं कि देश में इस नीति के दायरे में आने वाले वाहनों की संख्या चार से साढ़े चार करोड़ के बीच होगी जिनमें से आधे से कम वाहन ही उम्र की सीमा के अन्दर हैं। जाहिर है काफी सारे वाहन जिला पंजीयन कार्यालय की पहुंच और जानकारी से भी बाहर होंगे। कार को कबाड़ मानकर तोड़ना, गलाना और उसके मु–ी भर धातुओं का दोबारा इस्तेमाल करने से बेहतर तो यही है कि किसी तरह उसमें इस्तेमाल हुई चीजों का तब तक अधिकतम इस्तेमाल किया जाए जब तक वे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात ज्यादा प्रदूषण फैलाकर) हमारे लिए खतरा न बन जाएं. यह कल्पना भी आसान नहीं है कि भारत जैसे गरीब मुल्क में बनी गाड़ियों में से दो करोड़ से ज्यादा को हमारी ही सरकार कबाड़ बनाने जा रही है। एक तो भारत जैसे देश में इतनी गाड़ियों के बनने चलने और सार्वजनिक परिवहन की इस दुर्गति पर भी सवाल उठने चाहिए। इतनी गाडियों से रोड टैक्स वसूलने के बाद भी टोल टैक्स वसूली वाली सड़कों पर सवाल उठने चाहिए। लेकिन इनमें से कोई सवाल इतना बड़ा नहीं है कि एक साथ दो–ढाई करोड़ ऐसी गाड़ियों को कबाड़ घोषित करके गिनती की कम्पनियों को मालामाल करने के फैसले पर सवाल उठाने की बात भुला दी जाए।

प्रशासन की मनमानी

राघव शक्ति मिलन में रथ छतिग्रस्त, अब भरत मिलाप, उलझन में 'रामलीला'–लगाया ये आरोप

गोरखपुर। रामलीला कमेटी बर्डघाट के पदाधिकारियों ने कहा कि सपा समर्थित पार्षद और उनके पक्ष के लोगों ने राघव शक्ति मिलन पर अराजकता की। अब भरत मिलाप होना है। इसके पहले शिकायत पर भी इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब अगर भरत मिलाप में किसी तरह की बाधा या रुकावट इनके द्वारा पहुंचाई गई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। श्री श्री रामलीला कमेटी के महामंत्री हरिद्वार वर्मा ने बुधवार को कहा कि रावण दहन के बाद राघव–शक्ति मिलन के लिए जा रहे भगवान श्रीराम के रथ को रोक कर पार्षद लाली गुप्ता ने आरती करने का प्रयास किया, वह ठीक नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहा, भरत मिलाप का कार्यक्रम होना है। इसमें किसी प्रकार की बेतुकी हरकत हुई अथवा कोई अप्रिय घटना घटी तो इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन और सपा समर्थित पार्षद ही जिम्मेदार होंगे। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है।

बताया, श्रीराम लीला कमेटी की तरफ से पिछले 162 वर्षों से प्रभु श्रीराम की बारात, रामलीला का मंचन, दुर्गा शक्ति मिलन, भरत मिलाप और प्रभु के राजगद्दी का भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। इतने वर्षों ने किसी स्थानीय पार्षद, सदस्य, नागरिक, किसी भी संगठन या अधिकारियों की तरफ से कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रही, बल्कि हमेशा प्रभु श्रीराम के भव्य आयोजन को और दिव्य बनाए जाने में सभी ने अपना सहयोग दिया। आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि पिछले छह महीने में स्थानीय पार्षद(पहली बार चुनी गई) की तरफ से पहले राम लीला कमेटी पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। आरोप की जांच और रामलीला कमेटी के प्रपत्रों की जांच के बाद प्रशासन की तरफ से भी शिथिलता बरती गई।

अगर जांच में कमेटी की तरफ से किसी प्रकार की कोई गलती सामने आती तो प्रशासन को रामलीला मंचन बंद करवा इस परिसर को अपने कब्जे में लेकर हम सभी पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन, अगर लगाए आरोप कहीं भी सहीं नहीं मिले तो बार–बार आरोप लगाकरा प्रभु श्रीराम के नाम की कमेटी पर आरोप लगाने वाले पर आखिर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जैसा कि, पिछले दिनों फिर पार्षद की तरफ से श्रीराम लीला मंचन के दौरान ही गलत तथ्यों के साथ श्रीराम लीला कमेटी पर आरोप लगाए गए थे और इसपर कार्रवाई करवाई गई थी। ये तो अधिकारियों की समझदारी थी कि वो सच्चाई जानकर तत्काल अपने फैसले को वापस ले लिए। अगर प्रभु के मंचन के बीच में ऐसे गलत आरोप लगाए गए तो आखिर इसके पीछे क्या मंशा होगी ?

कर्जमाफी की अफवाह पर कार्रवाई

गोरखपुर। आरोप है कि आंबेडकर जनमोर्चा के पदाधिकारियों की ओर से गांव–गांव जाकर फर्जी कर्जमाफी की सूचना प्रसारित कर दी गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह सूचना तेजी से वायरल होने लगी। आरोप लगाया गया है कि कर्ज माफ करने के नाम पर एक फॉर्म को भरने के लिए 500 रुपये भी महिलाओं से वसूले गए। कर्जमाफी की अफवाह के मामले में महराजगंज के बाद अब गोरखपुर में भी केस दर्ज किया गया है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का लोन माफ करने की झूठी सूचना देकर महिलाओं से वसूली के आरोप में आंबेडकर जनमोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा और संयोजक श्रवण निराला पर बुधवार को गोरखनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के डिविजनल हेड ऋतु साहू ने केस दर्ज कराया है। मंगलवार को महाराजगंज के फरेंदा थाने में भी दोनों पर केस दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी श्रवण निराला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोप है कि आंबेडकर जनमोर्चा के पदाधिकारियों की ओर से गांव–गांव जाकर फर्जी कर्जमाफी की सूचना प्रसारित कर दी गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह सूचना तेजी से वायरल होने लगी। आरोप लगाया गया है कि कर्ज माफ करने के नाम पर एक फॉर्म को भरने के लिए 500 रुपये भी महिलाओं से वसूले गए।

यही नहीं, कर्जमाफी का फॉर्म सीएम कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर में जमा करने की सूचना भी महिलाओं को दे दी गई। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं गोरखनाथ मंदिर पहुंचने लगीं। उन्हें रोजाना ही गोरखनाथ मंदिर गेट से पुलिस समझाकर लौटा रही थी। इसमें अधिकतर महिलाएं महराजगंज से आई थीं, इस वजह से गोरखपुर पुलिस ने महराजगंज पुलिस को सूचना दी थी।

अवैध सोना: धंधेबाजों की भी दिवाली– फर्जी हालमार्किंग के जरिए खपा रहे अवैध सोना

गोरखपुर। रअसल, धंधेबाज भी जान गए हैं कि ग्राहकों को हॉलमार्क वाले आभूषणों की खरीदारी ही भा रही है। ऐसे में उन्होंने भी बीच का रास्ता निकाला है। अब अवैध सोने से बने आभूषणों को खपाने के लिए इसपर फर्जी हॉलमार्किंग लगवा दे रहे हैं। जबकि, बैंक से खरीदे सोने (जीएसटी फर्म पर) से तैयार आभूषणों पर फर्म के नाम से बने बिल (जीएसटी नंबर के साथ) वाली बिलिंग कर रहे हैं। दिवाली को लेकर अभी से सोने–चांदी के मार्केट में तेजी आ गई है। ऐसे में धंधेबाज भी अपनी दिवाली जगमग करने में जुट गए हैं। जिले के अलग–अलग गहना बाजारों में फर्जी हॉलमार्किंग के जरिए धंधेबाज अवैध सोना खपा रहे हैं। रोजाना करीब 25 किलो सोना के आभूषण इधर से उधर किए जा रहे हैं। शहर के ऐसे सात धंधेबाजों पर एजेंसियों की नजर है।

त्योहार के बीच ही इनपर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में अगर आप गहनों की खरीदारी कर रहे हैं तो पर्याप्त सावधानी बरतें। सूत्रों के मुताबिक, धंधेबाजों ने चोरी से खुद की दुकान पर ही हॉलमार्किंग मशीन लगाकर एचएम–750 बीआईएस का मार्का लगाकर आभूषण तैयार करना शुरू कर दिया है। इसमें हिंदी बाजार के पांच और आर्यनगर के दो धंधेबाज शामिल हैं। लगभग 16 किलो बुलियन में अवैध सोना गोरखपुर के बाजारों में पहुंच रहा है। ऐसे लगभग 22 करोड़ रुपये के अवैध सोने से आभूषण तैयार कर इसे बिना जीएसटी वाले बिलिंग पर्ची (कच्ची पर्ची) से ग्राहकों को बेचा जा रहा है। ये खपत त्योहार के समय और बढ़ जाएगी। दरअसल, धंधेबाज भी जान गए हैं कि ग्राहकों को हॉलमार्क वाले आभूषणों की खरीदारी ही भा रही है। ऐसे में उन्होंने भी बीच का रास्ता निकाला है। अब अवैध सोने से बने आभूषणों को खपाने के लिए इसपर फर्जी हॉलमार्किंग लगवा दे रहे हैं।

जबकि, बैंक से खरीदे सोने (जीएसटी फर्म पर) से तैयार आभूषणों पर फर्म के नाम से बने बिल (जीएसटी नंबर के साथ) वाली बिलिंग कर रहे हैं। बीआईएस को इसकी जानकारी भी मिली है। इसका फायदा है कि अवैध सोने के आभूषणों को बैंक के भाव वाले दर पर ग्राहकों को बेच देते हैं। ग्राहक भी बैंक के भाव वाले दर से सस्ते के चक्कर में कच्ची पर्ची पर ही इस आभूषण को खरीद लेते हैं, लेकिन इसमें फायदा धंधेबाजों का ही होता है।

जबकि, नियमानुसार ग्राहकों को पक्के पर्ची वाले बिल (जीएसटी बिल) ही दुकानदार से लेने चाहिए।

अध्यक्ष के नाम पर ही बेची जा रही थी फर्जी हालमार्किंग

हिंदी बाजार में धंधेबाजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक धंधेबाज के पास सराफा के अध्यक्ष की दुकान के नाम के फर्जी हॉलमार्किंग वाले जेवर रखे मिले थे। धंधेबाज ने बंधेल के जेवरों पर हॉलमार्किंग कराई थी। शिकायत पर पुलिस के साथ सराफा संगठन की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई थी। केस दर्ज कर कार्रवाई की गई थी।

बीआईएस केयर एप से ग्राहक खुद कर सकते हैं जानकारी

ग्राहक खुद अपने स्तर से ही तय कर सकते हैं कि गहने नकली तो नहीं। जैसे, ग्राहक किसी दुकानदार के पास गया। अगर दुकानदार बाजार भाव से कम पर आभूषण बेच रहा है तो पहले देखें कि बिलिंग पर्ची कैसी दी है। कच्ची है या पक्की। इसके बाद मोबाइल में बीआईएस केयर एप से ग्राहक हॉलमार्किंग की जांच खुद कर सकते हैं।शुद्धता जांचने के लिए ज्वेलरी का एचयूआईडी नंबर डालकर एप के वेरिफाई एचयूआईडी को जांचना होगा। बीआईएस की ओर से पंजीकृत दुकानदार होगा तो आईएसआई, हॉलमार्क और सीआरएस पंजीकरण चिह्नों की प्रामाणिकता एप पर दिख जाएगी।

त्योहार में बीआईएस ने 200 दुकानदारों को दी बड़ी राहत

त्योहार के बीच भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सोने–चांदी के 200 व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। ये वे व्यापारी हैं, जिनका बीआईएस मानक पंजीकरण सस्पेंड हो गया था। वे फीस जमा कर फिर से अपने पंजीकरण को करवाने के चक्कर में थे। अब बीआईएस ने त्योहारों को देखते हुए उनके पूर्व के लाइसेंस नंबर की वैधता बढ़ा दी है। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा। सिर्फ अपने बीआईएस हॉलमार्क नंबर के साथ जाकर अपने आभूषणों पर एचयूआईडी मार्का करा सकते हैं। एबी हॉलमार्किंग सेंटर के सीईओ पवन वर्मा ने बताया कि बीआईएस के इस फैसले से बहुत से व्यापारियों को राहत मिली है।

बजट में पास तो कर दिया, लेकिन लिखित आदेश नहल आया

सराफा मंडल के अध्यक्ष गणेश वर्मा ने बताया कि बजट में सोने पर लगने वाले कर में 6 प्रतिशत की छूट दी गई थी, लेकिन अभी इसे लेकर शासन की तरफ से लिखित आदेश नहीं आया है। बैंक से पहले वाले कर के भाव से ही खरीद–बिक्री हो रही है। इसका फायदा धंधेबाज उठा रहे हैं। अवैध सोने की खरीद, बैंक के भाव से सस्ती पड़ती है। ऐसे में अभी भी पहले की तरह ही सोना खप रहा है। ग्राहकों को चाहिए कि बीआईएस मानक के अनुरूप नहीं होने पर सराफा कमेटी से शिकायत कर सकते हैं।

दुकान छोटी, सौदा बड़ा

शहर के हिंदी बाजार से लेकर आर्यनगर इलाके और रुस्तमपुर क्षेत्र में दुकानें छोटी होने के बाद भी धंधेबाजों का धंधा बड़ा है। ये अवैध सोने के आभूषणों पर फर्जी हॉलमार्किंग लगाकर आस–पास के क्षेत्रों में आपूर्ति दे रहे हैं। इससे ग्रामीण अंचल में इनके आभूषण की खपत हो जा रही है।

सोने पर बैंक के भाव से दाम मिल जा रहा है। धंधेबाजी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस समय बैंक के सोने का भाव 77,730 रुपये प्रति दस ग्राम है, जबकि धंधे वाले सोने का भाव 77,600 हजार रुपये प्रति दस ग्राम। ऐसे में कुल 300 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता है। ये तब होता है, जब बाजार में धंधेबाजी वाले सोने की मांग औसत से कम हो जाती है। इस समय गोरखपुर की तुलना में धंधेबाजी वाला सोना नेपाल में खूब खपाया जा रहा है। इस वजह से गोरखपुर और आस–पास में इसका भाव कम हो गया है।

नेपाल में प्रति दस ग्राम 5 हजार रुपये अधिक का भाव

इन दिनों गोरखपुर की तुलना में यहां से नेपाल में सोने की तस्करी खूब हो रही है। गोरखपुर में सोने का भाव अगर 78 हजार रुपये प्रति दस ग्राम है तो नेपाल में इसका भाव भारतीय मुद्रा में 83 हजार रुपये होगा। ऐसे प्रति दस ग्राम 5 हजार रुपये अधिक के भाव से नेपाल में सोना खपाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों नेपाल से भारत में प्रवेश करने के बाद डीआरआई ने कुछ लोगों को अवैध सोने के साथ पकड़ा था। सूत्र ने बताया कि ये नेपाल से ही सोना खपाकर लौट रहे थे। इनके पास से बचे सोने और नकदी को एजेंसी ने पकड़ा था।

गोरखपुर नगर निगम फरवरी में बनी सड़क...

रातों–रात ठेकेदार ने जेसीबी से उखाड़ी, मलबा भी हटवाया

गोरखपुर। दिग्विजयनगर में 24 दिसंबर 2022 को पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने विनोद शाह के मकान से बलवंत के मकान तक सीसी सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया था। तब यह वार्ड संख्या 12 हुमांयूपुर था। फरवरी 2024 में 13 लाख रुपये से 120 मीटर लंबी सीसी सड़क बनाई गई। मंगलवार देर रात जेसीबी और ट्रैक्टर–ट्रॉली लगा कर सड़क तोड़ी जाने लगी।शहर के वार्ड नंबर 16 दिग्विजयनगर में इसी साल फरवरी में बनी सड़क को मंगलवार की रात ठेकेदार ने जेसीबी लगाकर उखाड़ दी। रातों–रात उसका मलबा भी हटवा दिया। लोगों ने सुबह सड़क देखकर पार्षद ऋषि मोहन वर्मा को सूचित किया। पार्षद ने निरीक्षण कर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल को इससे अवगत कराया। दिग्विजयनगर में 24 दिसंबर 2022 को पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने विनोद शाह के मकान से बलवंत के मकान तक सीसी सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया था। तब यह वार्ड संख्या 12 हुमांयूपुर था। फरवरी 2024 में 13 लाख रुपये से 120 मीटर लंबी सीसी सड़क बनाई गई। मंगलवार देर रात जेसीबी और ट्रैक्टर–ट्रॉली लगा कर सड़क तोड़ी जाने लगी। सुबह स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर पार्षद ऋषि मोहन वर्मा पहुंचे तो जेसीबी और ट्रैक्टर–ट्रॉली वाले आधा मलबा मौके पर छोड़ गाड़ी लेकर फरार हो गए। सड़क टूटने से लोगों में काफी नाराजगी है।

बुधवार को जांच के लिए अधिशासी अभियंता अमरनाथ, सहायक अभियंता शैलेष कुमार, अवर अभियंता विवेकानंद एवं अवनीश भारती मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद मुख्य अभियंता को अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात कही।

बुधवार को उन्होंने जांच की तो पता चला कि तोड़ी गई सड़क का वार्ड नंबर 74 संत झूलेलाल नगर के ट्रासंफॉर्मर से कुंज बिहारी (245 मीटर) के आवास तक त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत सीसी सड़क एवं नाला का प्रस्ताव स्वीकृत करा निविदा करा दी गई थी। निविदा हासिल करने वाले ठेकेदार ने बिना अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता के संज्ञान में लाए मंगलवार रात सड़क उखाड़ दी।

तैयार हो रहा रामगढ़ताल

20 प्रदेशों से आएंगी टीमें– रोइंग के रोमांच का आनंद ले सकेंगे लोग

गोरखपुर। टीमें 21 और 22 अक्तूबर को गोरखपुर पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में सबसे बड़ा दल महाराष्ट्र से आ रहा है। वहां से 24 बालक व 20 बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। हरियाणा से 29, पश्चिम बंगाल से 27, केरल से 24, पंजाब से 17, झारखंड व हरियाणा से 16–16, तमिलनाडु से 14, उड़ीसा से 11 खिलाड़ी शामिल होंगे। यूपी से कुल चार खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करेंगे, इसमें एक गोरखपुर से है। बालक और बालिका वर्ग में पांच–पांच इवेंट आयोजित होंगे।

रामगढ़ताल में गोरखपुरवासियों को 22 से 26 अक्तूबर तक रोइंग का रोमांच देखने को मिलेगा। 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप को लेकर तैयारियां जारी हैं। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव 23 अक्तूबर को औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। आयोजन सचिव पुनीत बालियान ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए 20 प्रदेशों की टीमों ने अपना पंजीकरण कराया है। बालक व बालिका वर्ग में कुल 240 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इनमें 136 बालक व 114 बालिका खिलाड़ी शामिल हैं। इन टीमों के साथ कुल 33 ऑफिशियल्स होंगे। प्रतियोगिता के लिए ज्यूरी 19 अक्तूबर को गोरखपुर आ जाएगी। उसी दिन से रामगढ़ताल में जूरी की निगरानी में रामगढ़ताल में कोर्स लाइन तैयार की जाएगी। टीमें 21 और 22 अक्तूबर को गोरखपुर पहुंचेंगी। वहां से 24 बालक व 20 बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। हरियाणा से 29, पश्चिम बंगाल से 27, केरल से 24, पंजाब से 17, झारखंड व हरियाणा से 16–16, तमिलनाडु से 14, उड़ीसा से 11 खिलाड़ी शामिल होंगे। यूपी से कुल चार खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करेंगे, इसमें एक गोरखपुर से है। बालक और बालिका वर्ग में पांच–पांच इवेंट आयोजित होंगे।

सभी प्रतियोगिताएं 500 मीटर में होंगी। सिंगल स्कल्स, डबल स्कल्स, कॉक्सलेस पेयर और कॉक्सलेस 4, अंडर 13 डबल स्कल्स प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

आरएसओ आले हैदर ने बताया कि रामगढ़ताल में 22 अक्तूबर से शुरू हो रही सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और होटलों में खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया गेम्स की तरह ही भव्य आयोजन होगा।

कुंभ मेला में अपनों से बिछड़ना बीते दिनों की बात, तकनीक के साथ

नई कहानी लिखेगी योगी सरकार

योगी सरकार की पहल से महाकुंभ में सुरक्षित रहेंगे आप के अपने।

महाकुंभ २०२५ में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सरकार ने ऐसे डिजिटल खोया-पाया केंद्रों की स्थापना करेगा जो खोए हुए व्यक्तियों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए तकनीक का सहारा लेते हैं। इसमें हर खोए हुए व्यक्ति का पंजीकरण तुरंत किया जाएगा और उसकी जानकारी को अन्य केंद्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और एक्स (पहले ट्वीटर) पर भी प्रसारित किया जाएगा।

लखनऊ। भारतीय सिनेमा में कुंभ मेला का जिक्र होते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले वही क्लासिक कहानियां आती हैं, जहां भाई–भाई, मां–बेटा या प्रेमी–प्रेमिका भीड़ में एक–दूसरे से बिछड़ जाते थे। यह बिछड़ने का दृश्य बॉलीवुड की कई पुरानी फिल्मों में बड़े भावनात्मक मोड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। योगी सरकार 'फिल्मी महाकुंभ' में लोगों के खोने और फिर सालों बाद मिलने की इस धारणा को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। अब कुंभ मेले में हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाएगा, कोई भी अब अपनों से नहीं बिछड़ेगा और ऐसा हुआ भी तो वह जल्द से जल्द अपने परिवार से मिल सकेगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और पुलिस विभाग ने मिलकर इस बार के महाकुंभ मेले में एक उच्च तकनीक से युक्त खोया–पाया पंजीकरण प्रणाली से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित करेगा। यह नई पहल सुरक्षा, जिम्मेदारी और तकनीक का अद्भुत संगम है, जो महाकुंभ मेला को सुरक्षित और सुखद अनुभव बना देगी।

योगी सरकार की पहल अब उस 'फिल्मी ड्रामे' को हकीकत से दूर ले जाकर सुरक्षा और पुनर्मिलन की नई कहानी लिखने को तैयार है। कुंभ मेले में आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों को अब भीड़ में खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार की यह नई प्रणाली खोए हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और शीघ्र उनके परिजनों से मिलाने का भरोसा देगी।

अब नहल होंगे `कुंभ के मेले में बिछड़ने' वाले दृश्य

भारतीय सिनेमा में कुंभ मेले की भीड़ से अलग हुए लोगों की कहानियां एक स्थायी कथानक रही हैं। फिल्मों में गंभीर संवाद हो या हास्य, कहीं न कहीं कुंभ मेले में बिछड़ने वाले डायलॉग सुनने को मिल ही जाते हैं। चाहे वो 1943 में आई फिल्म 'तकदीर' हो या 70 के दशक में आई फिल्म 'मेला'। इनमें भाइयों का मेले में बिछड़ने की कहानी सिनेमा के पर्दे पर वर्षों तक दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। इन कहानियों का मुख्य आधार यही था कि भीड़ में खो जाने के बाद, अपने प्रियजनों को खोज पाना लगभग असंभव होता था।

लेकिन अब इस हाई–टेक खोया–पाया केंद्र की बदौलत, महाकुंभ मेले में ऐसा 'फिल्मी' बिछड़ने वाला दृश्य शायद ही देखने को मिले। इन केंद्रों में खोए हुए व्यक्तियों का डिजिटल पंजीकरण होगा, जिससे उनके परिवार या मित्र आसानी से उन्हें खोज सकेंगे। साथ ही सभी लापता व्यक्तियों के लिए केंद्रों पर उद्घोषणा की जायेगी। पहले जहां एक मेला कई परिवारों के लिए बिछड़ने और असहाय खोज की दुखभरी गाथा लेकर आता था, अब वही मेला उनके पुनर्मिलन की एक नई कहानी लिखने जा रहा है।

तकनीक के साथ नई कहानी

महाकुंभ 2025 में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सरकार ने ऐसे डिजिटल खोया–पाया केंद्रों की स्थापना करेगा जो खोए हुए व्यक्तियों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए तकनीक का सहारा लेते हैं। इसमें हर खोए हुए व्यक्ति का पंजीकरण तुरंत किया जाएगा और उसकी जानकारी को अन्य केंद्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और एक्स (पहले ट्वीटर) पर भी प्रसारित किया जाएगा। यह व्यवस्था महाकुंभ मेले को न केवल सुरक्षित बनाएगी, बल्कि परिवारों को जल्दी और आसानी से अपने प्रियजनों से जोड़ने का काम करेगी। जहां फिल्मी कहानियों में खोए हुए व्यक्तियों को ढूंढने में सालों लग जाते थे, वहीं अब 12 घंटे के भीतर अगर कोई अपने खोए हुए सदस्य का दावा नहीं करता है, तो पुलिस हस्तक्षेप करके उन्हें सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक खोया हुआ महसूस न करे, और वह जल्द से जल्द अपने परिवार से मिल सके।

तीर्थयात्रियों के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था

पुरानी फिल्मों में, कुंभ मेले में बिछड़ने के बाद अक्सर परिवारों का मिलन संयोग पर आधारित होता थाकृकिसी चमत्कार या किस्मत के भरोसे। लेकिन अब योगी सरकार की इस नई पहल के तहत हर खोए हुए व्यक्ति की पहचान और सुरक्षा की जिम्मेदारी खोया–पाया केंद्र और पुलिस की होगी। खासतौर पर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी वयस्क को बच्चे या महिला का दावा करने पर पहले उनकी पहचान की पुष्टि करनी होगी। अगर कोई संदेह होता है तो तत्काल पुलिस को सूचित किया जाएगा ताकि बच्चा या महिला सुरक्षित हाथों में जाए। यह व्यवस्था उन फिल्मी कहानियों को पूरी तरह बदल देती है, जहां खोए हुए बच्चे को गलत हाथों में सौंप दिया जाता था और उसके जीवन में नाटकीय बदलाव आते थे।

पहचान प्रमाणित करने पर ही प्रशासन सौंपेगा खोया व्यक्ति

अब, जब कोई व्यक्ति कुंभ मेले में खोता है तो उसे सुरक्षित, व्यवस्थित और जिम्मेदार प्रणाली के तहत उसका ख्याल रखा जाएगा। किसी भी वयस्क को बच्चे या महिला को ले जाने से पहले सुनिश्चित करना होगा कि वह उसे पहचानते हैं और उनकी पहचान प्रमाणित है। इससे पहले की कहानियों में जहां बिछड़ने का दर्द और फिर मिलने की खुशी का एक लंबा सफर होता था, अब सरकार की इस पहल ने इस प्रक्रिया को सरल, तेज और सुरक्षित बना दिया है।

'राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से जीते...', यह बात कहने पर भड़के सपा विधायक, उंगली दिखाने पर हुई तू-तू मैं-मैं

कानपुर। कानपुर में सपा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल और महानगर अध्यक्ष फजल महमूद से विधायक अमिताभ और हसन रूमी भिड़ गए। महानगर अध्यक्ष के उंगली दिखाने पर विधायक ने कहा कि तमीज से बात करो। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सपा की समीक्षा बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। यहां सपा विधायकों, प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। पहले पार्टी के आर्यनगर क्षेत्र के विधायक अमिताभ बाजपेई अपने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की बात पर उखड़ गए। इसके बाद महानगर अध्यक्ष फजल महमूद ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के महानगर आने से कैंट की हारी हुई सीट पार्टी की जीत में बदल गई।

इस बात से कैंट के सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी भी भड़क उठे। महानगर अध्यक्ष फजल महमूद उंगली दिखाकर बात करने से मामला और बिगड़ गया। इस पर विधायक अमिताभ बाजपेई और हसन रूमी ने कहा कि तमीज से बात करो। विधायकों के विरोध को देखते हुए उनके समर्थकों ने भी मंच पर आकर नारेबाजी शुरू कर दी। बैठक में रूमी का कहना रहा कि उनकी जीत को सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से क्यों जोड़ रहे हैं। अमिताभ बाजपेई ने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल से कहा कि समीक्षा बैठक में ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। वहीं, जब विधायक अमिताभ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर कोई मनमुटाव और विरोध नहीं है। लेकिन हंगामे की बात पर वह चुप्पी साध गए। उधर, कैंट विधायक हसन रूमी ने तो अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लिया।

दरअसल, जिस समय प्रदेश अध्यक्ष सीसामऊ उप चुनाव को लेकर बनाई गई पदाधिकारियों की टीम की सूची लेकर समीक्षा कर रहे थे उसी समय अमिताभ बाजपेई ने माइक से बोला कि जिन पदाधिकारियों की सूची प्रदेश अध्यक्ष लेकर आए हैं, वही सूची जिला और पुलिस प्रशासन के पास भी। उन सभी को प्रशासन की ओर से परेशान किया जा रहा है। ऐसे में समीक्षा बैठक खुले में नहीं बंद कमरे में की जानी चाहिए।

इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने अमिताभ से कहा कि यहां इस तरह की बात मत कीजिए। इस पर अमिताभ ने हाथ में पकड़े हुए माइक को झटके से टेबल पर फेंकने की स्टाइल में रख दिया और वहां से बाहर आ गए। उनके साथ उनके समर्थक भी नारेबाजी करते हुए निकल आए। इस मामले में महानगर अध्यक्ष फजल महमूद और राष्ट्रीय सचिव अपर्णा जैन ने दोनों विधायकों पर दोष मढ़ते हुए इसकी शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष से करने की बात कही।

ऊपर की जाएगी शिकायत

पार्टी के दोनों विधायकों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की वजह से 2022 और लोकसभा चुनाव में सपा को बढ़त और जीत मिलने की बात करना अच्छा नहीं लगा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ करना इन्हें क्यों बुरा लगा, यह पता नहीं, लेकिन यह पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इसकी शिकायत ऊपर की जाएगी। – फजल महमूद, महानगर अध्यक्ष सपा

जीत में पार्टी का कोई योगदान नहीं

विधायक हसन रूमी को लगता है कि विधानसभा चुनाव में उनकी जीत उनके स्वयं की वजह से हुई है, इसमें पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई योगदान नहीं है। यही वजह है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रचार में आने से सपा के तीन प्रत्याशियों के जीतने की बात मंच से की जा रही थी, तब हसन रूमी विरोध करने लगे। – अपर्णा जैन, राष्ट्रीय सचिव सपा

पार्टी में मनमुटाव नहीं

पार्टी के अंदर किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, सभी लोग एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। – अमिताभ बाजपेई, विधायक

फर्जी एनकाउंटर कर विपक्ष पर दबाव बना रही प्रदेश सरकार – श्यामलाल

सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तैयारी को लेकर सपा ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक व पीडीए मिशन युवा टीम का सम्मेलन चमनगंज में किया। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि यह उपचुनाव प्रदेश भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। पाटी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी रिकार्ड मतों से जीत हासिल करेंगी। सरकार विपक्ष के नेताओं व कार्यकर्ताओं का फर्जी एनकाउंटर करके दबाव बना रही है। सांसद जितेंद्र दोहरे ने कहा कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। सपा विधानसभा क्षेत्र प्रभारी राजेंद्र कुमार ने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता की कमर टूट गई है। महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने आरोप लगाया कि सपा कार्यकर्ताओं को फोन करके धमकी दी जा रही है। इस मौके पर सह प्रभारी प्रेम प्रकाश वर्मा, प्रत्याशी नसीम सोलंकी, महासचिव संजय सिंह बंटी सेंगर, पूर्व सांसद राजाराम पाल, विधायक अमिताभ बाजपेई, मो. हसन रुमी, पूर्व विधायक दिलीप सिंह कल्लू, सतीश निगम, राष्ट्रीय सचिव अपर्णा जैन, प्रदेश सचिव आशीष चौबे, शैलेंद्र यादव मिन्टू, सुजाउरहमान, अपर्णा जैन, नीतेंद्र यादव, ओमप्रकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे।

बहराइच में 41 वर्ष पहले भी इस बात पर हुआ था बवाल

बहराइच। बहराइच के महराजगंज कस्बे में बीते रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान पथराव के बाद रेहुवा निवासी रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिंसा की यह आग धीरे–धीरे पूरे जिले में फैली। लोगों के घर जले। रिश्ते झुलसे। तपिश सद्भाव तक भी पहुंची। चार दिनों तक जनजीवन प्रभावित रहा। लोग घरों में कैद रहे। आज से 41 वर्ष पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। संयोग से महीना भी अक्तूबर ही था। तब दो समुदायों के बीच जमीन के एक हिस्से को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था। दंगे में दो लोगों की जान गई और करीब 19 घायल हुए। इनमें आम जनता के साथ ड्यूटी पर मुस्तैद तीन पुलिस जवान भी घायल हुए थे।

पार्टियों ने शुरू कईं तैयारियां, टिकट घोषित करने में सपा सबसे आगे

चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही प्रदेश की प्रमुख पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई थी।

इन सीटों पर होने हैं उपचुनाव

यूपी में करहल (मैनपुरी), सीसामऊ (कानपुर), मिल्कीपुर (अयोध्या), कटेहरी (अंबेडकरनगर), कुंदरकी (मुरादाबाद), खैर (अलीगढ़), गाजियाबाद, फूलपुर (प्रयागराज), मझवा (मिर्जापुर) और मीरापुर (मुजफ्फरनगर) पर उपचुनाव होने हैं। सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से रिक्त हुई है जबकि 9 विधायक, लोकसभा सदस्य बन चुके हैं।

लखनऊ। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही चुनावी जंग में कूदने वाले सभी सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही भाजपा, सपा और बसपा ने अपनी–अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी जबकि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर असमंजस से कांग्रेस दोराहे पर खड़ी दिख रही है। सपा तो पांच सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर चुकी है।

यूपी की नौ सीटों पर उपचुनाव

यूपी में विधानसभा की 10 में से नौ सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। नौ सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी।

इन सीटों पर होने हैं उपचुनाव

यूपी में करहल (मैनपुरी), सीसामऊ (कानपुर), मिल्कीपुर (अयोध्या), कटेहरी (अंबेडकरनगर), कुंदरकी (मुरादाबाद), खैर (अलीगढ़), गाजियाबाद, फूलपुर (प्रयागराज), मझवा (मिर्जापुर) और मीरापुर (मुजफ्फरनगर) पर उपचुनाव होने हैं। सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से रिक्त हुई है जबकि 9 विधायक, लोकसभा सदस्य बन चुके हैं।

भाजपा: पार्टी व संगठन तैयार, प्रत्याशी का इंतजार

विधानसभा उप चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही भाजपा अगले चरण की चुनावी तैयारी में जुट गई है। सरकार और संगठन ने पहले चरण की तैयारी काफी पहले पूरी कर चुकी है । पार्टी की तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो सरकार और संगठन ने मिलकर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर राजोगार मेला, जनसभा, बूथ प्रबंधन समेत सभी तैयारियों क पूरी कर चुकी है। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में हैं। प्रदेश संगठन की ओर से हर सीट के लिए तीन–तीन नाम का पैनल केन्द्रीय नेतृत्व को भेजा जा चुका है। संभावना है कि जल्द ही केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। इसलिए माना जा रहा है कि एक–दो दिन में भाजपा भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उप चुनाव की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले रखी है और उन्होंने अब तक सभी 10 सीटों पर दो से चार बार चक्कर लगा चुके हैं।

अधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक करके फीडबैक ले चुके हैं। बूथ तक के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के साथ ही सीएम जिला, तहसील और ब्लाक स्तरीय संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। यहीं नहीं करीब एक महीने पहले ही सीएम ने सरकार के 30 मंत्रियों की टीम बनाकर मैदान में उतार चुके हैं।

हर सीट की तीन–तीन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सीएम, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने भी दो–दो सीटों का प्रभार ले रखा है ।

मिल्कीपुर समेत छह सीटों पर सपा घोषित कर चुकी है प्रत्याशी

प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। पार्टी मिल्कीपुर समेत छह सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी हैं, हालांकि फिलहाल मिल्कीपुर का चुनाव टल गया है। यदि कांग्रेस से सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो सपा बाकी चार सीटों पर भी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। हालांकि कांग्रेस को दो सीट देने पर बातचीत का दौर जारी है।

बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरह सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता समाप्त होने की वजह से रिक्त हुई सीट पर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। इसके अलावा फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, कटेहरी से शोभावती वर्मा और मझवां सीट से डॉ. ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है।

गठबंधन कायम रखते हुए बची सीटों पर लगी कांग्रेस की निगाह

प्रदेश की नौ विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में पांच सीटों पर सपा उम्मीदवार उतार चुकी है। अब कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाने की दुहाई देते हुए बची चार सीटों पर निगाह लगाए हुए हैं। उसे उम्मीद है कि कम से कम दो सीटें उसे मिल सकती है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने मझवां, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी और मीरापुर सीट पर दावा किया था। सपा ने मझवां, फूलपुर सहित पांच सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाने की दुहाई दे रही है। साथ ही बाकी बची चार सीटों में से कुछ सीटों मिलने की बात कह रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसे कम से कम दो सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि उन्होंने पांच सीटों पर प्रस्ताव भेजा था। अभी चार सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। कुछ सीटों उन्हें जरूर मिलेंगी। हालांकि वह कहते हैं कि भाजपा के शासन से प्रदेशवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए सपा के साथ गठबंधन जरूरी है। कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाते हुए निरंतर भाजपा के खिलाफ संघर्ष करेगी।

बसपा बना चुकी है प्रभारी, तैयारियां जोरों पर

बहुजन समाज पार्टी बीते तीन माह से उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है। पार्टी ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिन्हें अब उपचुनाव की तारीख की घोषणा के बाद प्रत्याशी बना दिया जाएगा। बता दें कि बसपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। अपने अस्तित्व को बचाने को जूझ रही बसपा आगामी उपचुनाव में पूरी दमदारी के साथ उतरने जा रही है ताकि उसके हिस्से में भी कुछ सीटें आ सकें। जल्द ही बसपा सुप्रीमो मायावती इस संबंध में अहम घोषणा कर सकती हैं।

साख बचाने को सपा ने झोंकी ताकत

प्रतिष्ठा बचाने के लिए सपा ने झोंकी ताकत, पीडीए पर भरोसा
पीडीए के नेताओं को सौंप रखी है सीसामऊ सीट की कमान
18 अक्टूबर को कानपुर आएंगे प्रदेश अध्यक्ष

संवाददाता, कानपुर। सीसामऊ विधानसभा सीट पर उप चुनाव की घोषणा से पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपने कील–कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। प्रत्याशी की घोषणा करने के साथ ही सपा ने अपने पीडीए जनाधार को मजबूत करने के लिए आधा दर्जन नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है। बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती परखने के लिए भी प्रदेश स्तर से समीक्षा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी 18 अक्टूबर को सीसामऊ पहुंच रहे हैं। सीसामऊ सीट पर उप चुनाव की शुरुआती तैयारी में सपा की टीम भाजपा से पिछड़ते दिखाई दी लेकिन अब सपा के तेवर से साफ दिखने लगा है कि वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा की टीम अभी तक संगठन की तैयारी ही कर रही है जबकि प्रत्याशी की घोषणा करने के साथ ही सपा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी शुरू कर दी है।

जोनवार सौंपी गई जिम्मेदारी

चुनाव के लिए कई स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है। विधायकों और महानगर अध्यक्ष समेत प्रमुख पदाधिकारियों को जोनवार जिम्मेदारी दी गई है। पांच जोन में बूथ व मंडल अध्यक्षों के साथ जोन प्रभारी और उनके सहायक भी तैनात कर दिए गए हैं।

चुनाव प्रभारी के साथ सह प्रभारी भी

सीसामऊ सीट पर चुनाव की रणनीति इस बार सपा के लखनऊ मुख्यालय में बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए पार्टी नेतृत्व ने जोनवार जिम्मेदारी सौंपी और मानीटरिंग की कमान अपने हाथ में ले रखी है। चुनाव प्रभारी राजेंद्र कुमार के साथ सह प्रभारियों की टीम भी लगाई गई है, जिसमें इटावा के सांसद जितेंद्र दोहरे, प्रदेश महासचिव प्रेम प्रकाश वर्मा, पूर्व विधायक गजाला लारी, पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन, विधायक विशंभर यादव शामिल हैं।

पीडीए पर रहेगा दांव

सपा के महानगर अध्यक्ष फजल महमूद ने सीसामऊ को सपा की पारंपरिक सीट बताते हुए कहा कि पीडीए पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। पीडीए के नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इस मतदाता वर्ग ने लोकसभा चुनाव में सपा को अभूतपूर्व समर्थन दिया है और इस बार उप चुनाव में भी साथ मिलने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के आने से चुनाव अभियान को और मजबूती मिलेगी।

हिन्दू युवती को षडयंत्र के तहत भगाकर ले गया आशिक अंसारी, गांव में तनाव का माहौल

संवाद सूत्र, बिथरी/बरेली। हिंदू युवती को षड्यंत्र के तहत फंसाकर आशिक अंसारी अपने साथ भगा ले गया। युवती के पिता ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए मतांतरण की आशंका जाहिर की है। पिता के शिकायती पत्र पर बिथरी थाने में आरोपित और उसके परिवार वालों के विरुद्ध अपहरण व मतांतरण दोनों की धाराओं में प्राथमिकी लिखाई है। तनाव का माहौल देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। पुलिस की दो टीमें युवती को बरामद करने में जुट गई हैं।

बिथरी थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी सोमवार सुबह 11 बजे कहीं चली गयी थी। उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया मगर उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। मंगलवार को उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को गांव का ही आशिक अंसारी षड्यंत्र के तहत अपने साथ भगाकर ले गया। उसे भगाने में आशिक के पूरे परिवार वालों का सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी लव जिहाद की शिकार हुई है।

> **मामले में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। अपहरण और मतांतरण दोनों की धाराएं लगाई गईं हैं। दोनों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही दोनों को बरामद किया जाएगा**
> **–मुकेश मिश्र, एसपी नार्थ**

पिता ने बेटी के मतांतरण की आशंका व्यक्त की

पिता ने आशंका जाहिर की कि उनके बेटी का मतांतरण भी कराया जा सकता है। इसके बाद कोई अनहोनी हो सकती है। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी घर से एक सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, दो जोड़ी चांदी की पायल और 10 हजार रुपये लेकर गई है। मामले में जैसे ही प्राथमिकी पंजीकृत हुई और हिंदू संगठनों को लव जिहाद के बारे में जानकारी हुई तो गांव के लोग थाने पर पहुंच गए। उन्होंने बेटी को जल्द से जल्द बरामद करने की बात कही। उधर, दूसरी ओर धीरे–धीरे गांव में भी तनाव का माहौल पैदा होने लगा। हालातों को समझते हुए प्राथमिकी में मतांतरण व अपहरण दोनों की धाराएं लगाई हैं। साथ ही गांव में किसी भी तरह की कोई हिंसा न भड़के इसलिए फोर्स भी तैनात किया गया है।

युवती को ढूंढने को लगी टीमें

सीओ हाईवे नितिन कुमार ने बताया कि युवती और युवक दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। उनकी लोकेशन ट्रेस करने की तैयारी कर रही है। दो टीमों को उसे ढूंढने को लगा दिया गया है। जल्द ही दोनों को बरामद किया जाएगा। पिता बोले– आशिक की बहन का था आना जाना युवती के पिता ने बताया कि उनके घर पर आशिक की बहन का आना जाना था। वह ही काफी देर तक उनके घर पर रहा करती थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसकी बहन ने ही युवती का ब्रेन वाश किया है जिसकी वजह से वह घर से भागी है। पुलिस ने आशिक के परिवार वालों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया लेकिन वह दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। पुलिस आशिक के पिता से लगातार पूछताछ कर रही है।

यूपी में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर खड़े ट्रेलर के पीछे घुसी बलेनो कार

हाईवे पर खड़े ट्रेलर के पीछे बलेनो कार घुसी, तीन की मौत
स्पीड इतनी तेज थी कि एयर बैग खुलने के बावजूद गई जान

संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर–प्रयागराज हाईवे पर कल्यानपुर थाने के बड़ौरी टोल प्लाजा के समीप मंगलवार सुबह दस बजे तेज रफ्तार बलेनो कार खड़े ट्रेलर के पीछे जा घुसी। जिससे चालक समेत सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइविंग सीट में फंसे चालक व पीछे बैठे दो युवकों को बाहर निकाला तो तीनों मृत थे। पुलिस के मुताबिक कार की स्पीड इतनी तेज थी कि एयर बैग खुल जाने के बावजूद तीनों की जान चली गई। एसओ रमाशंकर सरोज ने बताया कि दिवंगतों में 64 वर्षीय व्यक्ति की शिनाख्त कन्नौज जिले के युसुफपुर निवासी अभिनाश चंद्र दुबे के रूप में की गई है जो कन्नौज में स्थित गोमती गर्ल्स इंटर कालेज के प्रबंधक बताए गए हैं। वहीं कन्नौज के ही इनके साथी की शिनाख्त 65 वर्षीय मनोज शुक्ला के रूप में की गई। चालक की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी प्रयागराज किसी काम से जा रहे थे। पहिए में हवा भरवाने के लिए पत्थर लदा ट्रेलर खड़ा था। जिसे पकड़ लिया गया है।

जम्मू–कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 के आए नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। जिसके बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। केंद्र शासित प्रदेश में उमर अब्दुल्ला की सरकार भले ही बन गई है लेकिन सत्ता की असली चाबी उपराज्यपाल के हाथ में रहने वाली है।

जम्मू–कश्मीर में लागू है संविधान का अनुच्छेद 239। एलजी की अनुमति के बिना नहीं ले सकते कई फेसले एलजी की अनुमति के बिना नहीं पेश हो सकता कोई बिल

जम्मू। जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के सामने आए नतीजों में नेकां और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया। दोनों पार्टियों ने मिलकर 48 सीटें हासिल की। एनसी को 42 सीटें, तो कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। जिसके बाद आज यानी बुधवार को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उमर अब्दुल्ला वैसे तो पहले भी जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इस बार भले ही उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन इस सरकार की चाबी उपराज्यपाल के हाथ में होगी।

राज्यपाल की मंजूरी और अनुमति लेकर करना होगा काम

उमर अब्दुल्ला जनवरी 2009 से जनवरी 2015 तक जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे थे। हालांकि, उस समय जम्मू–कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। जम्मू–कश्मीर का अपना खुद का संविधान था। केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य सरकार की चलती थी। लेकिन अब जम्मू–कश्मीर एक राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है और यहां राज्य से ज्यादा केंद्र सरकार की चलेगी। यानी उमर अब्दुल्ला जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत से ऐसे फैसले हैं, जो राज्यपाल के मंजूरी और अनुमति लिए बगैर नहीं कर पाएंगे।

2019 में पास हुआ था जम्मू–कश्मीर रिकार्गनाइजेशन एक्ट

साल 2019 में जम्मू–कश्मीर रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट पास हुआ था। जिसके बाद राज्य को जम्मू–कश्मीर और लद्दाख, दो हिस्सों में बांटकर दोनों को अलग–अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा नहीं है, लेकिन जम्मू–कश्मीर में विधानसभा है। संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के पास होता है। जिसके लिए राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रशासक नियुक्त करता है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख में राज्यपाल होते हैं, जबकि दिल्ली, अंडमान–निकोबार, पुडुचेरी और जम्मू–कश्मीर में उपराज्यपाल होते हैं।

बदल चुकी है जम्मू–कश्मीर की संवैधानिक संरचना

जम्मू–कश्मीर में भी पुडुचेरी की तरह संविधान का अनुच्छेद 239। लागू है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, जहां 239।। लागू है। इसलिए दिल्ली में पुलिस, जमीन और कानून–व्यवस्था के अलावा सभी मामलों में दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि, जम्मू–कश्मीर में ऐसा नहीं है। जम्मू–कश्मीर रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट 2019 के आने के बाद जम्मू–कश्मीर की संवैधानिक संरचना पूरी तरह बदल चुकी है और अब यहां सरकार से ज्यादा बड़ी भूमिका उपराज्यपाल की है। जम्मू–कश्मीर की सरकार पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर सभी मामलों में कानून बना सकती है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान देना होगा कि इससे केंद्रीय कानून पर कोई असर न पड़े। इसके अलावा, कोई भी बिल या संशोधन विधानसभा में बिना राज्यपाल की मंजूरी के पेश नहीं किया जा सकता है।

उपराज्यपाल के पास कितनी शक्तियां?

साधारण भाषा में आप उपराज्यपाल की शक्तियों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जम्मू–कश्मीर में सरकार किसी की भी हो उपराज्यपाल ही सबकुछ है। जम्मू–कश्मीर की सरकार को कोई भी बिल विधानसभा में पेश करने, कोई भी कानून बनाने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेना आवश्यक है। यानी कोई भी बिल या कानून बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के जम्मू–कश्मीर की सरकार नहीं बना सकती है। इसके अलावा उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही सरकारी अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जा सकता है। जम्मू–कश्मीर की सरकार उपराज्यपाल के किसी भी काम की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकती है। उपराज्यपाल ने कोई भी फैसला लेते वक्त मंत्री परिषद की सलाह ली थी या नहीं, इस आधार पर उनके फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जम्मू–कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 से पहले ही उपराज्यपाल को एडवोकेट जनरल और लॉ अफसरों की नियुक्ति करने का अधिकार मिल गया था। जम्मू–कश्मीर में पहले 6 साल का कार्यकाल होता था, लेकिन अब हर 5 साल के कार्यकाल के बाद चुनाव होंगे। बता दें कि फिलहाल जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं।

नई दिल्ली। आज केंद्र की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में किसानों के लिए कई फैसले लिये गए हैं। आज की बैठक में किसानों के लिए अहम फैसले लिये गए हैं। कैबिनेट ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025–26 के लिए एमएसपी को लेकर भी फैसला लिया है। बता दें कि कैबिनेट ने 6 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी है।

इन फसलों की बढ़ी एमएसपी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि फसलों की एमएसपी पर 300 रुपये प्रति क्विंटल तक का इजाफा किया गया है। वहीं फसलों की मार्जिन लागत में भी 50 फीसदी का इजाफा किया गया। आइए, जानते हैं कि कैबिनेट ने फसलों पर कितनी एमएसपी बढ़ाई–

आंखों से पट्टी हटी

सुप्रीम कोर्ट में 'लेडी आफ जस्टिस' यानी न्याय की देवी की नई मूत लगाई गई है। इस मूत की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। वही, उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है।

विस्तार के लिए गीता प्रेस ने संस्कृति मंत्रालय से मांगी 20 एकड़ जमीन, धन की कमी बनी बाधा

विस्तार के लिए जमीन की जरूरत, धन की कमी बनी बाधा
गीडा में पसंद आई जमीन, कीमत लगभग 72 करोड़ रुपये

20 एकड़ जमीन के लिए लगभग 72 करोड़ रुपये चाहिए, क्योंकि वहां जमीन की कीमत प्रति वर्गमीटर नौ हजार रुपये है। इतने रुपये गीताप्रेस के पास नहल्ल हैं। इसलिए प्रेस प्रबंधन ने संस्कृति मंत्रालय को पत्र लिखकर चैरिटी संस्थानों की तरह गीताप्रेस को जमीन देने की मांग की है। निर्माण कार्य प्रेस स्वयं कराएगा।

"हमारे पास जमीन खरीदने के लिए कोई मद नहीं है। प्रेस का काम चैरिटी ही है। इसलिए संस्कृति मंत्रालय से चैरिटी संस्थानों की तरह गीताप्रेस को जमीन देने के लिए अनुरोध किया गया है।"

देवी दयाल अग्रवाल
ट्रस्टी, गीताप्रेस

"वासंतिक व शारदीय नवरात्र में श्रीदुर्गासिप्तशती की मांग हर साल बढ़ जाती है। इस साल सबसे ज्यादा मांग "श्रीदुर्गासिप्तशती सचित्र" की रही। यह पुस्तक सस्ती होने के साथ ही आकर्षक भी है, क्योंकि इसकी छपाई विशिष्ट पेपर पर की गई है। पिछले साल के दोनों नवरात्रों में इस पुस्तक की 161445 प्रतियां बिकी थीं। इस वर्ष के दोनों नवरात्र में इसकी 179399 प्रतियां बिकी हैं।"

डा. लालमणि तिवारी
प्रबंधक, गीताप्रेस

संवाददाता, गोरखपुर। गीताप्रेस के विस्तार के लिए जमीन खरीदना प्रबंधन के सामने चुनौती है। जिला प्रशासन से नाउम्मीद होने के बाद प्रेस प्रबंधन ने स्वयं जमीन की तलाश शुरू की। गीडा में जमीन पसंद भी आ गई, लेकिन उसकी कीमत चुनौती बनकर खड़ी हो गई।

20 एकड़ जमीन के लिए लगभग 72 करोड़ रुपये चाहिए, क्योंकि वहां जमीन की कीमत प्रति वर्गमीटर नौ हजार रुपये है। इतने रुपये गीताप्रेस के पास नहीं हैं। इसलिए प्रेस प्रबंधन ने संस्कृति मंत्रालय को पत्र लिखकर चैरिटी संस्थानों की तरह गीताप्रेस को जमीन देने की मांग की है। निर्माण कार्य प्रेस स्वयं कराएगा।

गीताप्रेस न तो कभी मांगता है और न ही दान स्वीकार करता है। लोक कल्याण के लिए उसने संस्कृति मंत्रालय से जमीन की अपेक्षा की है, ताकि सौ साल पूरा कर चुका गीताप्रेस अगले सौ वर्षों तक लोगों को लागत मूल्य से कम में धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध करा सके और विश्व के अनेक देशों में भारतीय धर्म–संस्कृति की सुगंध पहुंचा सके।

इसके लिए प्रेस को 20 एकड़ जमीन की जरूरत है। गीडा में जाकर प्रेस प्रबंधन ने कई जमीन देखी लेकिन वहां 20 एकड़ जमीन की कीमत लगभग 72 करोड़ रुपये है।

यह जमीन गीडा कार्यालय के पास है। वहां 25 एकड़ जमीन है, जिसमें से पांच एकड़ गीडा अपने लिए आरक्षित रखेगा, शेष 20 एकड़ इंस्टीट्यूशनल कार्य के लिए आवंटित कर सकता है। यह जमीन तो प्रबंधन को पसंद आ गई, लेकिन इसके लिए गीताप्रेस के पास न तो कोई मद है और न ही

इतने रुपये जमीन खरीदने के लिए हैं। गीडा ने गीताप्रेस को संत कबीर चौरा, मगहर रोड पर भी लगभग 5.75 एकड़ जमीन दिखाई, यह जमीन छोटी होने से प्रबंधन को पसंद नहीं आई।

चार लाख पाठकों तक पहुंची श्रीदुर्गासप्तशती

देवी उपासना के पर्व नवरात्र में श्रीदुर्गासप्तशती की चार लाख प्रतियां पाठकों तक पहुंच गईं। यह संख्या पिछले साल के बराबर ही है, लेकिन इस बार विशिष्ट पेपर पर प्रकाशित "श्रीदुर्गासप्तशती सचित्र" की मांग सबसे ज्यादा रही। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष इस पुस्तक की लगभग 18 हजार प्रतियां अधिक बिकीं। वासंतिक व शारदीय नवरात्र के दौरान प्रेस को श्रीदुर्गासप्तशती की बिक्री से लगभग 2.88 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसकी कीमत 80 रुपये है। श्रीदुर्गासप्तशती अनेक आकार–प्रकार व स्वरूप में प्रकाशित की जाती है। इनका मूल्य 30 रुपये से लेकर 450 रुपये तक है। गीताप्रेस लागत से कम मूल्य पर पूरी शुद्धता के साथ धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। इस प्रेस की पुस्तकें अन्य प्रकाशनों की अपेक्षा ज्यादा सस्ती होती हैं, गुणवत्ता में कमी नहीं होती और भाषा के स्तर पर पूरी तरह शुद्ध होती हैं। इसलिए गीताप्रेस से प्रकाशित पुस्तकों की मांग सबसे ज्यादा है। वासंतिक नवरात्र अप्रैल में और शारदीय नवरात्र अक्टूबर में पड़ा था। इस दौरान श्रीदुर्गासप्तशती पुस्तक की मांग बढ़ जाती है। इसलिए इसकी तैयारी पहले से गीताप्रेस ने कर ली थी।शारदीय नवरात्र के लिए दो लाख प्रतियां पहले ही प्रकाशित कर ली गई थीं, जो नवरात्र शुरू होने के पूर्व ही खत्म हो गईं। पाठकों की मांग को देखते हुए प्रेस ने आनन–फानन 40 हजार प्रतियों का और प्रकाशन किया। वे सभी नवरात्र के दौरान ही डिस्पैच कर दी गईं।

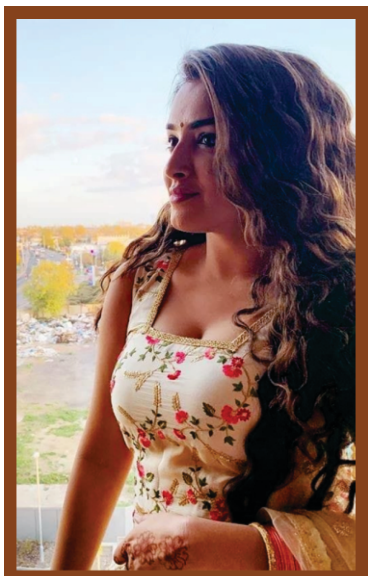

आम्रपाली दुबे की आगामी फिल्म की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। आम्रपाली दुबे भोजपुरी की सबसे सीनियर अभिनेत्री है और हर कोई उनकी फिल्मों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता नजर आता है। जिस किसी ने भी आम्रपाली दुबे के खूबसूरत अंदाज को इस फिल्म के शूटिंग सेट पर देखा है तब सभी लोग अब बहुत ही बेसब्री के साथ इस फिल्म का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं।

"हर निर्माता पैसा कम देना चाहता है। कोई लिहाज नहीं करता। अब कॉरपोरेट कल्चर आ गया है। उन्हें मालूम ही नहीं है, कौन क्या है। वो बस फोन उठाकर बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं"।

-अखिलेंद्र मिश्रा

इस इंडस्ट्री में पैसा सिर्फ स्टार्स के पास है, क्योंकि निर्माता उन्हें ही देते हैं। आज भी कैरेक्टर आर्टिस्ट अगर अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो उनके पास दवाई के पैसे नहीं होते, उन्हें इकठ्ठा करने पड़ते हैं। कई ऐसे म्यूजिशियन, आर्ट डायरेक्टर और यहां तक कि एक्टर्स भी हैं, जो गुमनामी और गरीबी में मर जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। पैसे सिर्फ स्टार और प्रोड्यूसर कमाते हैं और कोई नहीं कमाता है"। उन्होंने ये भी कहा कि लोग तुलना हॉलीवुड से करने बैठते हैं, तो फिर सबकी रॉयल्टी फिक्स करो। हॉलीवुड में जो सेट पर पानी भी देते हैं, उनके अकाउंट में भी उन्हें बताए बिना सीधे रॉयल्टी भेज दी जाती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अपने इस इंटरव्यू को खत्म करते हुए अखिलेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस बात को बोलने के बाद अब मैं सबका दुश्मन बन जाऊंगा।

बिग बास के कप्तान ने घरवालों को दिया काम.

बिग बास के कप्तान ने घरवालों को दिया काम.

विवियन–चाहत का फिर हुआ आमना–सामना, 1–2 नहीं 10 कंटेस्टेंट हुए नामिनेट

नई दिल्ली। बिग बॉस 18 के पहले वीकेंड का वार में गधराज घर से बाहर हो गया. उसके बाद दशहरा की वजह से किसी घरवाले को घर से बेघर नहीं होना पड़ा. अब बिग बॉस में एक और हफ्ता बीतने के बाद घरवालों के सिर पर एविक्शन की तलवार लटक रही है. इस बार एक या दो नहीं बल्कि 10 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस 18 में सबसे पहले किसका सफर खत्म होगा, तो चलिए बताते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या–क्या ड्रामा हुआ.

बिग बॉस की शुरुआत से दो ऐसे घरवाले हैं जिनकी लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. वो दोनों विवियन डिसेना और चाहत पांडे हैं. पहले दिन से ही ये दोनों किसी न किसी बात पर लड़े जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर अविनाश मिश्रा भी किसी न किसी से लड़ते–झगड़ते रहते हैं. बीते एपिसोड में अविनाश मिश्रा और शिल्पा शिरोडकर के बीच जमकर बहसबाजी हुई. ये झगड़ा खत्म ही हुआ था कि एलिस कौशिक और श्रुतिका आपस में भीड़ गए.

कप्तान ने सुनाया फैसला

14 अक्टूबर के एपिसोड में अरफीन को घर का पहला कैप्टन चुना गया जिसके बाद कल उन्होंने बाकी सभी घरवालों के बीच ड्यूटी का बंटवारा किया. साथ ही उन्होंने नॉमिनेशन का भी खुलासा किया. वो कहते हैं कि ये सभी फैसले उनके निजी हैं. न वो किसी की बातों में आते हैं और ना ही किसी की कोई बात सुनना चाहते हैं.

चाहत पांडे और ईशा सिंह के बीच हुआ घमासान

चाहत घर में हर बात ;पर हंसती रहती हैं, ऐसे में कई बार घरवालों को लगता है कि शायद चाहत उनपर हंस रही हैं. ईशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने चाहत से उनसे दूर रहन एके लिए कहा जिसपर वो खट्टी हैं कि वो क्यों दूर हटें ये घर उनका भी है. यहीं से बात बिगड़ जाती है वुर वो दोनों लड़ने लग जाती हैं.

अरफीन उनमें सुलह करा देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही ईशा इस मुद्दे को विवियन के साथ डिस्कस करते हुए रोने लग जाती हैं. वो कहती हैं कि चाहत गंवार की तरह हंसती हैं. इसपर विवियन उन्हें समझाते हैं कि जितना ह्जो सके चाहत को इग्नोर करें और यही सबसे अच्छा तरीका है.

कंबल पर हुई लड़ा

विवियन घर के कप्तान अरफीन से कहते हैं कि लिविंग रूम में कोई सामान नहीं फैला होना चाहिए. इसपर चाहत बीच में बोलने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि वो अपना सारा सामना हटाकर स्टोरेज रूम में रख देंगी, लेकिन उनका कंबल वहीं लिविंग रूम म एं ही रहेगा, वो अपनी बात पर अड़ जाती हैं और यहीं से बहस छिड़ जाती है.

गुणरत्न `बिग बश्वस 18´ से बाहर

बिग बॉस गुणरत्न सदावर्ते को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कोर्ट में उनका केस चल रहा है. उसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाया जाएगा। 10 लोगों के नॉमिनेट होने के बाद अविनाश मिश्रा के नाम को लेकर चर्चा बढ़ गई है कि शायद इस बार घर से बाहर हो जाएं. दरअसल, शुरुआत से ही वो किसी न किसी से लड़ते दिख रहे हैं.

क्या समांथा को मिला नया प्यार

एक्स पति की सगाई के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि समांथा रुथ प्रभु भी अब यकीनन तौर पर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगी। अब मनोरंजन जगत में उनके नए ब्वॉयफ्रेंड को लेकर सुर्खियां तेज हैं। रेडिट पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि समांथा और राज निदिमोरू एक दूसरे को शायद डेट कर रहे हैं। हालांकि, इस बात की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है कि सच में ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। लेकिन इनके डेटिंग रूमर्स ने बी टाउन में खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया पर फैंस का मानना है कि नागा चैतन्य की तरह समांथा को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है। मालूम हो कि आने वाले समय में एक्ट्रेस वेब सीरीज सिटाडेल–हनी बनी में दिखेंगी, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन नजर आएंगे, ये सीरीज 7 नवंबर 2024 को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।

कौन हैं राज निदिमोरू

राज निदिमोरू ओटीटी की दुनिया के दिग्गज फिल्ममेकर हैं। राज एंड डीके क्रिएशन की जोड़ी का नाम आपने खूब सुना होगा, ये वही वाले राज हैं। अब तक ये दोनों द फैमिली मैन, फर्जी और गन्स एंड गुलाब्स जैसी कई शानदार वेब सीरीज को बना चुके हैं।

बता दें राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी स्त्री की कहानी को भी राज निदिमोरू ने ही लिखा था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 8 अगस्त को साउथ सिनेमा की सुपरस्टार समांथा रुथ प्रभु के एक्स हसबैंड नागा चैतन्य ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभिता धूलिपाला के साथ सगाई रचाई है। अब समांथा ने भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। खबर है कि सिटाडेल–हनी बनी वेब सीरीज एक्ट्रेस समांथा की जिंदगी में शायद नए प्यार की एंट्री हो गई है। रूमर्स हैं कि सिटाडेल निर्देशक राज निदिमोरू को समांथा रुथ प्रभु डेट कर रही हैं। आइए इस मामले को थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं।

लाइफ में हुई नए प्यार की एंट्री!

क्या समांथा रुथ प्रभु को मिल गया नया प्यार
सिडाटेल डायरेक्टर को डेट करने को लेकर चर्चा
एक्स हसबेंड नागा चैतन्य ने हाल ही में की सगा

संमाथा रुथ प्रभु का नाम इस वक्त कई वजहों से चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ उनके एक्स हसबेंड नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की सगाई और दूसरी तरफ वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी के चलते समांथा लाइमलाइट में हैं। अब खबर आ रही है कि समांथा की लजदगी में भी एक नए प्यार की एंट्री हो गई है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में विराट से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद

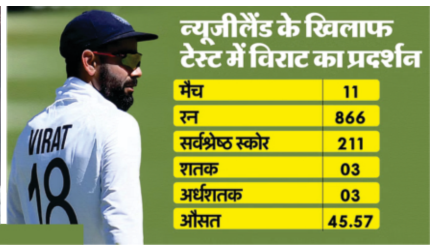

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से आगामी टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। किंग कोहली के पास अब टेस्ट क्रिकेट में नौ हजार रन पूरे करने का सुनहरा मौका है। वह ऐसा करने से सिर्फ 53 रन दूर है। फिलहाल वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में शीर्ष पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं।

पिछली आठ पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगा सके कोहली

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 16 अक्तूबर से शुरू होने जा रहे टेस्ट मुकाबले में भारतीय दिग्गज से बड़ी पारी की आस है। कोहली ने टेस्ट की पिछली आठ पारियों में सिर्फ एक बार अर्धशतक लगाया है। दिसंबर, 2023 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की दमदार पारी खेली थी। वहीं, बांग्लादेश के खिलाफ खत्म हुई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भी उनका बल्ला कुछ खास नहीं चला।

गंभीर ने जताया कोहली पर भरोसा

चेन्नई टेस्ट में पूर्व कप्तान ने पहली पारी में छह और दूसरी पारी में 17 रन बनाए। वहीं, कानपुर में उन्होंने पहली पारी में 47 रन और दूसरी पारी में नाबाद 29 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए शुरुआत से पहले गंभीर ने उम्मीद जताई कि आगामी सीरीज में वह अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। गंभीर ने कहा– कोहली को लेकर मेरी सोच एकदम स्पष्ट है कि वह विश्व स्तरीय क्रिकेटर हैं। उसने इतने साल से इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। रनों को लेकर उसकी भूख वैसी ही है जैसी पदार्पण के समय थी। मुझे याद है जब मैंने उनके डेब्यू पर श्रीलंका के खिलाफ कोहली के साथ साझेदारी की थी। उस समय में उनके अंदर रन बनाने की ऐसी ही भूख थी। यही भूख उसे विश्व स्तरीय क्रिकेटर बनाती है। मुझे यकीन है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में और फिर ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर–गावस्कर ट्रॉफी के दौरान भी रन बनाएगा।

कोहली ने इस वर्ष नहीं लगाया है कोई अर्धशतक

विराट ने इस वर्ष तीन टेस्ट मैच खेले हैं इनमें कोई अर्धशतक नहीं लगाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो 11 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने 45.57 के औसत से 866 रन बनाए हैं। वहीं, उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 211 का रहा है। कोहली ने कीवियों के खिलाफ इस प्रारूप में तीन शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर भारत का सफर शानदार ढंग से जारी है। 74.24 प्रतिशत अंकों के साथ भारतीय टीम लगातार तीसरे टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलने की सबसे बड़ी दावेदार है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में भी रोहित शर्मा की टीम को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। बांग्लादेश पर 2–0 से जीत के बाद भारतीय टीम सभी विभागों में खरी उतरी।

दनादन क्रिकेट का नया रोमांच...

एलएलसी टेन–10 की ट्राफी का अनावरण, कई दिग्गज रहे मौजूद

दी नेक्स्ट पोस्ट

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर गोरखपुर से मुद्रित एवं 665 बी गंगा टोला, निकट जानकी बिल्डिंग मैटेरियल बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर से प्रकाशित। पिनः– 273003

Tital code: UPHIN51019

बृजेन्द्र कुमार
मो0. नं0. 7307180148,9170772370
Email- thenextpost01@gmail.com

नोटः– समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद–विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगे।

स्पोर्ट्स डेस्क। दिग्गज क्रिकेटरों रवि शास्त्री, सैयद किरमानी और इरफान पठान की मौजूदगी में श्रीनगर में लीग की चमचमाती ट्रॉफी का दीदार। केंद्र सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एलएलसी टेन 10 का आयोजन किया जा रहा है। टेनिस बॉल से खेली जाने वाली इस लीग में 10–10 ओवरों के मुकाबले खेले जाएंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। एलएलसी टेन–10 लीग के जरिए उत्तर प्रदेश को दनादन क्रिकेट के रोमांच से सराबोर करने की तैयारियां शुरु हो चुकी हैं। लीजेंड्स लीग क्रिकेट और अमर उजाला की ओर से अगले माह नवंबर में यह लीग लखनऊ में आयोजित की जा रही है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के दौरान श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में दिग्गज रवि शास्त्री, सैयद किरमानी और इरफान पठान ने एलएलसी टेन–10 लीग की ट्रॉफी का अनावरण किया। ट्रॉफी के अनावरण के साथ लीग में खेलने के लिए क्रिकेटरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

क्या है एलएलसी टेन–10 ?

केंद्र सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एलएलसी टेन 10 का आयोजन किया जा रहा है। टेनिस बॉल से खेली जाने वाली इस लीग में 10–10 ओवरों के मुकाबले खेले जाएंगे।

इन शहरों की हैं टीम

लीग में खेलने वाली टीमों में आगरा की टीम जीएल बजाज नाइटराइडर्स, इन शहरों की हैं टीमें मार्वल्स और झांसी नोएडा की टीम जीएल बजाज सुपरकिंग्स, लखनऊ की टीम केरासा लखनऊ पैंथर्स, मुरादाबाद की टीम वेंकटेश्वरा लायंस मुरादाबाद माइटीवॉरियर्स, मेरठ की टीम आईआईएमटी मेरठ की टीम बुंदेलखंड ब्लास्टर्स होगी। गैलेंट इस्पात लिमिटेड के सीईओ मयंक अग्रवाल ने कहा, 'एलएलसी टेन–10 से जुड़कर उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश के युवा क्रिकेटरों में अपार प्रतिभा छुपी हुई है। उनमें कुछ कर दिखाने की कृवत है। लीग के रूप में इन युवाओं के लिए यह मंच अपनी प्रतिभा दिखाने का बहुत बड़ा अवसर है। प्रतिभा दिखाने के साथ युवा क्रिकेटरों को दिग्गज क्रिकेटरों से सीखने का भी मौका मिलेगा।'

ये हैं लीग के मेंटर

लीग में खेलने वाले क्रिकेटरों को दिग्गज क्रिकेटरों का मार्गदर्शन मिलेगा। लीग की टीमों के साथ बतौर मेंटर सुरेश रैना, हरभजन सिंह, क्रिस गेल, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान और ब्रेट ली जैसे महान क्रिकेटर जुड़ रहे हैं।

लखनऊ में होगी लीग

लीग को लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। नवंबर माह में होने वाली लीग की जल्द तिथि घोषित की जाएगी।

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

लीग से जुड़ने के लिए मंगलवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। लीग के लिए ससबजमद10.बवउ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

12 शहरों में होगा ट्रायल

रजिस्ट्रेशन के बाद टीमों के चयन के लिए ट्रायल उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद और बरेली शहरों में होंगे

रोहित–गंभीर के सामने टेस्ट खेलने की इच्छा जता चुके हैं संजू सैमसन

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत के बल्लेबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। फाइनल मैच में शतक के साथ वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। सैमसन ने कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर को टीम में अपना नैचुरल गेम खेलने की आजादी देने का श्रेय दिया। बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज में शतक लगाने वाले संजू सैमसन ने अब टेस्ट क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई है। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने ही किया है। सैमसन की अब तक व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया में जगह पक्की नहीं है। वह पिछले कुछ समय से टी20 टीम का तो हिस्सा हैं, लेकिन वनडे नहीं खेल रहे। भारतीय स्क्वॉड का तो वह कई बार हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन खेलने का मौका कम मिला है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले सैमसन अब तक सिर्फ 16 वनडे और 33 टी20 खेल सके हैं। हालांकि, अब उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर से टेस्ट में खेलने की इच्छा जताई। इस पर रोहित और गंभीर ने भी उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इन दोनों को लगता है कि सैमसन टेस्ट में अच्छा कर सकते हैं।

'टीम मैनेजमेंट ने रणजी खेलने की सलाह दी'

स्पोर्टस्टार के साथ एक इंटरव्यू में सैमसन ने बताया कि वह रेड–बॉल क्रिकेट में सफल होने के लिए कितने आश्वस्त हैं, लेकिन अभी भी इस प्रारूप में बीसीसीआई चयन समिति द्वारा मौका दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। सैमसन ने कहा, 'मेरा मानना है कि मेरे पास रेड बॉल क्रिकेट में सफल होने के लिए स्किल सेट है और मैं खुद को सफेद गेंद के क्रिकेट तक सीमित नहीं रखना चाहता। मेरी इच्छा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने की है। दलीप ट्रॉफी से पहले बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट (कप्तान–कोच समेत) ने मुझे बताया था कि वे टेस्ट क्रिकेट के लिए मेरे नाम पर विचार कर रहे थे और मुझे इसे गंभीरता से लेने और रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए कहा था।'

सैमसन ने गंभीर की तारीफ की

भारत के बल्लेबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। फाइनल मैच में शतक के साथ वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। सैमसन ने कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर को टीम में अपना नैचुरल गेम खेलने की आजादी देने का श्रेय दिया।

उन्होंने कहा, 'सूर्या अच्छे कम्युनिकेटर हैं और वह खिलाड़ियों से क्या चाहते हैं, इसको लेकर उनके अंदर स्पष्टता है। वह अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं और खिलाड़ी उन पर भरोसा करते हैं।

गौतम भाई ने हमेशा मेरा समर्थन किया है। जब आपके पास कोच के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी क्षमता पर विश्वास करता है, तो क्रिकेट खेलना अधिक सुखद हो जाता है।'

टीम मैनेजमेंट का सैमसन को खूब समर्थन मिला

"उन्होंने कहा, 'आम तौर पर जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो आप अपनी भूमिका को लेकर सुनिश्चित नहीं होते हैं। लेकिन इस बार, मुझे तीन सप्ताह पहले ही बता दिया गया था कि मुझे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलना है। मैं नई भूमिका के लिए मानसिक रूप से तैयार था।'